संयम ◆संस्कार ◆संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

शहर समता

वर्ष-22 अंक- 227
पृष्ठ 8
गुरूवार
07 मई 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

प्रयागराज से प्रकाशित Email : shaharsamta@gmail.com Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- लहसुन छीलने में अब नहीं...

विचार- सूचना का अधिकार : नियंत्रित...

खेल- पाकिस्तान सुपर लीग की टीम ऑफ...

राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं-मुख्यमंत्री योगी

प्रयागराज,संवाददाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लड़ाई सीमाओं से बढ़कर साइबर, स्पेस, डेटा नेटवर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक फैल चुकी है। पारंपरिक युद्ध कौशल के साथ-साथ अब तकनीकी दक्षता, रणनीतिक सोच और मानसिक दृढ़ता भी अनिवार्य हो गई है। आज के युद्ध में कीबोर्ड, सेटेलाइट और डेटा उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने पारंपरिक हथियार। दुश्मन के संचार नेटवर्क को बाधित करना तथा अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना नई युद्ध रणनीति का आधार बन रहा है। ऐसे परिदृश्य में वही राष्ट्र आगे रहेगा, जो साहस और तकनीक के बीच संतुलन स्थापित कर सके। "नेशन फर्स्ट" केवल एक नारा नहीं, बल्कि हर भारतीय सैनिक के जीवन का संकल्प है। यह हर नागरिक के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं।

सीएम योगी बुधवार को प्रयागराज में ष्क्षा त्रिवेणी संगमष की थीम पर नॉर्थ टेक सिम्पोजियम एनटीएस 2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि सियाचिन की जमाने वाली ठंड हो, रेगिस्तान की तपती रेत, घने जंगलों का अंधकार या समुद्र व आकाश की अनंत चुनौतियां, हमारे सैनिक हर परिस्थिति में तत्पर रहते हैं। उनकी सतर्क निगाहों के कारण ही पूरा देश सुरक्षित और निश्चिंत रह पाता है। आधुनिक युद्ध अब केवल जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के युग में प्रवेश कर चुका है। युद्ध में साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे क्षेत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। कीबोर्ड भी एक प्रभावी हथियार बन चुका है। दुश्मन के पावर ग्रिड, राडार, जीपीएस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करना या अपने नेटवर्क को सुरक्षित व अभेद्य बनाना, नई सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। सेटेलाइट्स के माध्यम से निगरानी, खुफिया जानकारी और नेविगेशन अब युद्ध की 'आंख' और 'दिमाग' बन चुके हैं। अब लड़ाई सिग्नल्स और डेटा के माध्यम से भी लड़ी जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर युद्ध जैसी स्थितियों ने यह स्पष्ट किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है। कुछ वर्ष पहले भारत का रक्षा निर्यात लगभग 600 करोड़ रुपये ही था, लेकिन निरंतर प्रयासों से आज हमारी सामर्थ्य 38 हजार से 50 हजार करोड़ रुपये तक के रक्षा उत्पाद निर्यात करने की है। भारत अब मित्र देशों को रक्षा उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छह प्रमुख नोड्स लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट पर तेजी से कार्य हो रहा है। इन नोड्स में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर रहे हैं। सरकार ने डिफेंस एवं एयरोस्पेस पॉलिसी के तहत बड़े लैंड बैंक का निर्माण किया है और निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अलीगढ़ छोटे हथियारों और रक्षा उपकरणों के निर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जबकि कानपुर गोला-बारूद, मिसाइल, डिफेंस टेक्सटाइल और प्रोटेक्टिव गियर के उत्पादन का हब बन रहा है। लखनऊ , झांसी नोड्स में ब्रह्मोस मिसाइल और हैवी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे देश की सैन्य क्षमता और मजबूत हो रही है। चित्रकूट और आगरा नोड्स में एयरोस्पेस और प्रिसिजन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकास जारी है, ताकि स्पेस डोमेन सहित रक्षा के सभी आयामों में देश की क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत तोप के गोले, स्वदेशी ड्रोन, बुलेटप्रूफ जैकेट और उन्नत संचार प्रणालियों का निर्माण किया जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए आवश्यक सुविधाएं उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। प्रदेश के पास 56 प्रतिशत युवा एवं स्किल्ड वर्कफोर्स और 96 लाख एमएसएमई इकाइयों का मजबूत आधार है, जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स पर पर्याप्त लैंड बैंक भी उपलब्ध है। राज्य सरकार स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केट-रेडी और इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स तैयार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में आईआईटी कानपुर के साथ ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया गया है, जबकि स्टेट फॉरेंसिक संस्थान के माध्यम से भी विभिन्न क्षेत्रों में नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। सभी स्ट्रेटेजिक नोड्स में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है।

भारत-वियतनाम का 2030 तक व्यापार का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी बोले- सप्लाई चेन होगी मजबूत

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को घोषणा की कि भारत और वियतनाम ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप को औपचारिक रूप दिया है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्र-विशिष्ट सहयोग में एक महत्वपूर्ण विस्तार का संकेत है। यह घोषणा तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के आदान-प्रदान को देखा। एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, प्रधानमंत्री ने बाजार पहुंच और व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपायों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आज 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे औषधि प्राधिकरणों के बीच समझौता ज्ञापन से अब वियतनाम में भारतीय दवाओं की पहुंच बढ़ेगी। वियतनाम को भारतीय कृषि, मत्स्य और पशु उत्पादों का निर्यात भी आसान होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कृषि आदान- प्रदान से जल्द ही दोनों देशों के उपभोक्ताओं को ठोस लाभ मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा, बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद चखेगा, और हम वियतनाम के पोमेलो का स्वाद चखेंगे।

कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी पार्षद गिरफ्तार

कोलकाता,एजेंसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वैध दस्तावेजों के बिना कारतूस ले जाने के एक पुराने मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान अमीरुल शेख इस्लाम के रूप में हुई है जो बज बज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुजाली नगरपालिका के वार्ड 14 से पार्षद है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को मंगलवार रात को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले साल सितंबर में वह एक विमान से उड़ान भरने के लिए कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचा था और उसके सामान से कारतूस बरामद हुआ था लेकिन वह निर्धारित समय में उसके लिए कोई वैध लाइसेंस दिखाने में असफल रहे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सब-इंस्पेक्टर गोपाल शॉ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार घटना 21 सितंबर, 2025 की है जब आरोपी इंडिगो की उड़ान में सवार होने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया नियमित सामान जांच के दौरान यात्री के सामान में एक मैगजीन के साथ 7.65 एमएम के छह कारतूस बरामद हुए थे। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने शुरू में दावा किया था कि उसके पास वैध लाइसेंस है और उसने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। अधिकारी ने कहा, चूंकि वह एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि है इसलिए उसे आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दिया गया था। हालांकि वह दिए गए समय के भीतर कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद हवाई अड्डे के थाने में शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया, वैध लाइसेंस के बिना कारतूस रखना दंडनीय अपराध है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

बिहार के छपरा में पिकअप वैन पलटने से उत्तर प्रदेश के चार आर्केस्ट्रा कर्मियों की मौत, छह घायल

छपरा,एजेंसी। बिहार के सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक तेज रफ्तार पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर पलटने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना छपरा-रिविलगंज मार्ग पर भगवान बाजार थाना के पीएन सिंह कॉलेज के पास हुई है। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, पिकअप में ऑर्केस्ट्रा कर्मी सवार थे। बताया गया कि एक मांगलिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर आर्केस्ट्रा टीम के लोग एक पिकअप वैन में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान न्याय बस्ती लोहा टोला के समीप पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। वाहन में कुल 10 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पिकअप वैन तेज रफ्तार से जा रही थी और सामने से उस समय एक ट्रक भी गुजर रहा था। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर ही चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत तथा बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को स्थानीय एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर धर्मेंद्र प्रधान का तंज, कहा-

बंगाल में लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर रखा जा रहा

नयी दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की हठधर्मिता की आलोचना की क्योंकि उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल को स्वेच्छा से अपना इस्तीफा सौंपने की संभावना से इनकार कर दिया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा जवाबदेही का विरोध और जनता के जनादेश को स्वीकार करने से इनकार करना इस बात का उदाहरण है कि बंगाल में लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर रखा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ष्बंगाल में लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर रखा जा रहा है और चुनावी नतीजों को मानने से इनकार करना इस वास्तविकता को उजागर करता है। जनादेश को जनता की आवाज की बजाय ऐसे सुझावों की तरह माना जा रहा है जिन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।

ममता बनर्जी द्वारा जनादेश की भावना को स्वीकार करने से इनकार करना एक गंभीर प्रश्न उठाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बंगाल की जनता को जनादेश के बाद विनम्रता की उम्मीद थी। लेकिन इसके बजाय हम तृणमूल कांग्रेस द्वारा जवाबदेही से बचने का प्रयास देख रहे हैं। सत्ता पर काबिज रहने की होड़ में ममता बनर्जी न केवल जनता के जनादेश को नकार रही हैं, बल्कि भारतीय चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी धूमिल करने का प्रयास कर रही हैं, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने वाले मूल स्तंभों को ही कमजोर किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार, बंगाल लंबे समय से एक ऐसे शासन मॉडल के अधीन रहा है जो धमकी, सिंडिकेट नेटवर्क और गहरे राजनीतिक संरक्षण से चिह्नित है। ममता का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, उनका विरोध कोई अपवाद नहीं है। यह उसी व्यवस्था की सबसे स्पष्ट पुष्टि है। सच्चा लोकतंत्रवादी जनता के सामने झुकता है। तानाशाह जनता की परवाह किए बिना सत्ता से चिपके रहता है। उन्होंने कहा कि बंगाल का जनादेश डर की अस्वीकृति, जबरदस्ती की अस्वीकृति और जवाबदेही की मांग है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसकी अनदेखी करना लोकतांत्रिक वैधता की बुनियाद को ही कमजोर करना है। भारत का संविधान शासन में हठधर्मिता को सद्गुण नहीं मानता। जवाबदेही अनिवार्य है और जनादेश पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह ऐसे समय में हुआ है जब भाजपा पश्चिम बंगाल में निर्णायक दो-तिहाई बहुमत के साथ अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिससे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो जाएगा। 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। सोमवार को 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित किए गए, जबकि दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा सीट पर 21 मई को पुनर्मतदान निर्धारित है। घोषित परिणामों में, भाजपा ने 206 सीटें हासिल कीं, जो तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे है, जिसे केवल 81 सीटें मिलीं।

भाजपा का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता : राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में भाजपा के हर छठे सांसद ने वोट चोरी के जरिए जीत हासिल की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए कहा कि वोट चोरी से कभी एक सीट चुराई जाती है और कभी पूरी सरकार। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसदों में लगभग हर छठा सांसद वोट चोरी करके पहुंचा है। उन्होंने भाजपा पर हमला तेज करते हुए कहा कि ऐसे सांसदों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सवाल किया कि क्या ऐसे लोगों को घुसपैठिया कहा जाना चाहिए। उन्होंने हरियाणा सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वहां पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर किया जा रहा है और जिन संस्थाओं को निष्पक्ष होना चाहिए, वे रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा को सबसे ज्यादा डर सच से लगता है। अगर आज निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो वे 140 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। इससे एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को जनादेश की चोरी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी ने टीएमसी का समर्थन करते हुए कहा कि टीएमसी की हार पर खुशी जताने वालों को छोटी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए।

तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा : राउत

मुंबई,एजेंसी। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद देश की राजनीति गरमा गई है। शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत ने निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। राउत ने कहा कि ममता बनर्जी का यह कदम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि यह केवल सत्ता का मोह नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की एक लड़ाई है। संजय राउत ने कहा कि देश में केंद्र की तानाशाही और चुनाव आयोग के पक्षपाती व्यवहार के खिलाफ एकजुट होना अब अनिवार्य हो गया है। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में चुनाव आयोग की आलोचना की। राउत ने आरोप लगाया कि वर्तमान में चुनाव संस्था पूरी तरह से केंद्र सरकार की गुलाम बन चुकी है। उन्होंने विपक्षी दलों से आह्वान किया कि अब यह तय करने का समय आ गया है कि भविष्य में चुनाव लड़ना भी है या नहीं। ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी।

उन्होंने बंगाल के चुनावी नतीजों को जनता का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी को साजिश के तहत हराया गया। 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 207 सीटें मिली हैं, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई है। ममता ने कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं, बल्कि पक्षपाती चुनाव आयोग से थी। राउत ने ममता के फैसले को सही ठहराते हुए 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट का उदाहरण दिया। उन्होंने याद दिलाया कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते, तो उनकी सरकार बहाल हो सकती थी।

देशभर में फ्री हेल्थ चेकअप

ईएसआईसी अस्पताल में 40 साल से अधिक उम्र के श्रमिकों को मिलेगा लाभ, मांडविया दिल्ली से करेंगे शुरुआत

नयी दिल्ली,एजेंसी। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया नए श्रम संहिताओं के तहत प्रस्तावित 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत बृहस्पतिवार को करेंगे। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस पहल का औपचारिक उद्घाटन नयी दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (बसईदारापुर) से किया जाएगा। देश भर में 11 अन्य ईएसआईसी अस्पतालों में भी एक साथ उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें संबंधित राज्यों के श्रम मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। यह पहल श्रमेव जयते के व्यापक ढांचे के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है जो श्रम की गरिमा एवं श्रमिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा पर जोर देता है। यह कार्यान्वयन चार नए श्रम संहिताओं के माध्यम से लाए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर आधारित है। इन संहिताओं में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित और ऑनलाइन मंच के लिए काम करने वाले

श्रमिकों को शामिल करती है। साथ ही इसमें एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रावधान है और ईएसआईसी लाभों के दायरे का विस्तार करती है। नई श्रम रूपरेखा के तहत एक प्रमुख प्रावधान 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच है। ईएसआई योजना के लाभार्थियों के लिए ये जांच ईएसआईसी के व्यापक अस्पताल नेटवर्क के माध्यम से की जाएंगी जिनमें प्रारंभिक निदान, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सतत स्वास्थ्य निगरानी पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, खतरनाक या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए आयु पर गौर किए बिना स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी।

तेज रफ्तार बाइक डीजे से टकराई, शादी में खाना बनाकर लौट रहे दो कारीगरों की मौत

करछना (प्रयागराज)। करछना थाना क्षेत्र के भीरपुर चौकी क्षेत्र के प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर नच्चू ढाबा के पास हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है। करछना थाना क्षेत्र के भीरपुर चौकी क्षेत्र के प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर नच्चू ढाबा के पास हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत

हो गई है। आशीष उर्फ छोटू (22) पुत्र ज्वाला सिंह निवासी सरपतहिया थाना नैनी अपने साथी शिवानंद केसरवानी (22) पुत्र दिनेश केसरवानी निवासी नैनी के साथ हलवाई का काम करने मेजा गया था। वहां से दोनों मंगलवार की रात लगभग एक बजे घर के लिए लौट रहे थे। रास्ते में नच्चू ढाबा के पास उनकी बाइक डीजे से टकरा गई।मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौकै पर पहुंच गई।

मदरसे की मान्यता रद्द करने का आदेश निरस्त, दोबारा सुनवाई के निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा प्रबंधन समिति की मान्यता रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है और मामले को पुनः विचार के लिए संबंधित प्राधिकारी के पास भेज दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां हुईं, जिससे याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर नहीं मिल सका। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने आजमगढ़ की कमेटी मैनेजमेंट ऑफ दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम और अन्य की याचिका पर दिया है। नौ जनवरी 2026 के आदेश से मदरसे की मान्यता रद्द कर दी गई थी। कमेटी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि सात जनवरी 2026 को याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर सात दिन का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया था। हालांकि, निर्धारित समय पूरा होने से पहले ही आदेश पारित कर दिया गया। यह भी दलील दी कि उन्हें समय दिया जाता तो वह धन के दुरुपयोग और कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोपों पर महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते थे। विवादित राशि पहले ही सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि नोटिस गलती से जारी हुआ था और बाद में उसे वापस ले लिया गया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याची का पक्ष सुने बिना आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने विवादित आदेश रद्द कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह का समय देकर नया जवाब मांगा जाए और संबंधित प्राधिकारी 14 दिनों में कारणयुक्त नया निर्णय पारित करें।

हाईकोर्ट ने चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की नई नियुक्तियों पर लगाई रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय कन्नौज में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदों पर की जा रहीं नई नियुक्तियों के संबंध में जारी विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने कन्नौज निवासी स्वेतांक अरुण की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम–2022 के तहत नियुक्ति दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए होती है, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल बढ़ाने से पहले संबंधित प्राधिकारी की ओर से कार्य का मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य है।

वर्तमान मामले में 22 जनवरी 2026 को कार्य रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन बिना किसी मूल्यांकन के अगले ही दिन 23 जनवरी को नए पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि विवादित विज्ञापन के क्रम में फिलहाल कोई नया अनुबंध निष्पादित न किया जाए। हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को यह छूट दी है कि वे याची के कार्य का उचित मूल्यांकन कर सकते हैं और प्रदर्शन संतोषजनक पाए जाने पर उनके कार्यकाल के विस्तार पर विचार कर सकते हैं।

रक्षा क्षेत्र में भारत अब निर्यातक की भूमिका में: डॉ. जितेंद्र सिंह

प्रयागराज। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पीएमओ डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को संगम नगरी में कहा कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। युद्ध कौशल केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि तकनीक, वास्तविक समय के डाटा सिस्टम और स्वचालित प्लेटफॉर्म से संचालित हो रहा है। बीते एक दशक में भारत दुनिया का बड़ा रक्षा आयातक होने की छवि को पीछे छोड़कर अब एक उभरते हुए निर्यातक के रूप में स्थापित हो चुका है।

न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में नार्थ टेक सिंपोजियम में डॉ. जितेंद्र सिंह ने आंकड़ों के जरिये रक्षा क्षेत्र की मजबूती को रेखांकित किया। बताया कि 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 174 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। चौंकाने वाली प्रगति निर्यात के मोर्चे पर रही है। इसमें 34 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपये के पार हो गया है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 15 हजार करोड़ रुपये है। यह बदलाव रक्षा विनिर्माण में सरकार और निजी उद्यमियों के बीच बढ़ते सहयोग का जीवंत प्रमाण है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए रक्षा बजट में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 6.81 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम तकनीक हमारी रक्षा तैयारियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। भारत ने क्वांटम–सुरक्षित संचार क्षमताओं में पहले ही तेजी से प्रगति की है, जो आने वाले समय में युद्ध प्रणालियों की रीढ़ बनेगी। सेना के तीनों अंगों, उद्योग जगत और शोध संस्थानों के बीच तालमेल पर जोर दिया ताकि डिजाइन से लेकर सेना में तैनाती तक के समय को कम किया जा सके।

रक्षा त्रिवेणी संगम में उमड़ा तकनीक का सैलाब

नार्थ टेक सिंपोजियम में 284 स्टालों पर अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री ने इसका जायजा भी लिया। उन्हें बताया गया कि यहां एआई, अनमैन्ड सिस्टम (ड्रोन), काउंटर–ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और साइबर युद्ध से जुड़ी प्रणालियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।

बरात में घुसी बेकाबू बोलेरो, दो की मौत, आठ घायल, द्वारचार के दौरान हुआ हादसा

फूलपुर (प्रयागराज)। फूलपुर थाना क्षेत्र के बौड़ई कटौता गांव में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। द्वारचार की रस्म के दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित बोलेरो कार बारातियों के बीच घुस गई। फूलपुर थाना क्षेत्र के बौड़ई कटौता गांव में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। द्वारचार की रस्म के दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित बोलेरो कार बारातियों के बीच घुस गई, जिससे मौके पर अफरा–तफरी मच गई। हादसे में रमेश (32) पुत्र हरिहर बौड़ई निवासी थाना फूलपुर और दीपांशू (12) निवासी खागा फतेहपुर की मौत हो गई। जबकि करीब आठ लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक रमेश लड़की पक्ष की तरफ से था जबकि दिपांशू डीजे के साथ आया था।

फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बौड़ई गांव निवासी शुकरू चौहान की दो बेटियों की शादी कानपुर देहात के उस्मानपुर जमराही निवासी पप्पू के पुत्र राहुल और दीपक के साथ तय थी। मंगलवार रात करीब 12 बजे बारात गांव पहुंची। स्वागत और नाश्ते के बाद बराती डीजे के

साथ लड़की पक्ष के दरवाजे पहुंचे, जहां पारंपरिक द्वारचार की रस्म चल रही थी।

रात करीब 2 बजे अधिकतर बाराती सड़क किनारे खड़े होकर कार्यक्रम देख रहे थे और डीजे भी वहीं लगा हुआ था। तभी प्रतापपुर–फूलपुर मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो अचानक अनियंत्रित हो गई और डीजे से टकराते हुए भीड़ को रौंदती चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों ओर चीख–पुकार मच गई और मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे आगे–पीछे दौड़ाते हुए भागने की कोशिश की, जिससे कई और लोग उसकी चपेट में आ गए। कुछ लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन समेत फरार हो गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और बरातियों ने सड़क पर हंगामा करते हुए कुछ वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, जिससे मार्ग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने के बावजूद पुलिस घंटे भर बाद मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात बहाल कराया।

घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में रमेश की मौत हो गई। वह मजदूरी कर परिवार का भरण–पोषण करता था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत से पत्नी और पांच बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

घायलों में इस्माइल (21), रत्नेश (10), अरशद, दीपू (17), रवि (18), साजन (65), कुंवर सिंह (18), रामवीर और दूल्हे के पिता पप्पू सहित कई लोग शामिल हैं। लड़की पक्ष से बादल (16) भी घायल हुआ है। दर्दनाक हादसे के बीच गमगीन माहौल में परिजनों ने सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए जल्दबाजी में विवाह की शेष रस्में पूरी कर दुल्हनों की विदाई कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और फरार बोलेरो चालक की तलाश जारी है।

इकलौते कमाने वाले की मौत से परिवार बेसहारा

रमेश की मौत से परिवार पर गहरा संकट आ गया है। वह मजदूरी कर घर चलाता था। अब पत्नी और पांच बच्चों के सामने जीवन यापन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

दूल्हे के पिता समेत कई गंभीर घायल

हादसे में दूल्हे के पिता पप्पू सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

भागने की कोशिश में और लोगों को रौंदा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने भागने के दौरान वाहन को आगे–पीछे दौड़ाया, जिससे कई और लोग घायल हो गए। इससे हादसे की भयावहता और बढ़ गई।

आक्रोश में सड़क जाम, पुलिस देर से पहुंची

घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस के देर से पहुंचने पर लोगों में और गुस्सा देखने को मिला।

गम के साए में पूरी हुई शादी

हादसे के बाद माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया, लेकिन सामाजिक मजबूरी के चलते परिजनों ने जल्दबाजी में विवाह की शेष रस्में पूरी कर दुल्हनों को विदा किया।

बड़े मंगल पर मंदिरों में दिनभर चला पूजा-पाठ और भंडारा

प्रयागराज। ज्येष्ठ माह के प्रथम बड़े मंगल पर मंगलवार को विभिन्न हनुमान मंदिरों में भक्ति और आस्था दिखी। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी और दिनभर पूजा–अर्चना, आरती व भंडारे का क्रम चलता रहा।

बड़े हनुमान मंदिर में सुबह चार बजे विशेष आरती के बाद हनुमान जी का फूलों से शृंगार किया गया। दिनभर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरि जी महाराज ने बताया कि मंदिर को फूलों से सजाया गया था और ढोल–ताशे के साथ हनुमानजी का भजन गाया गया।

सिविल लाइंस स्थित हनुमत निकेतन में सुबह पांच बजे आरती और विशेष शृंगार के बाद शाम को भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें भक्तों ने भक्ति गीतों का आनंद लिया। यहां भी प्रसाद वितरित हुआ।

इसी तरह संकटमोचन हनुमान मंदिर में शाम को सुंदरकांड पाठ हुआ। इसके बाद भंडारा हुआ। शाम पांच बजे विशेष आरती हुई। शिव मंदिर झलवा में भी सुबह आरती, सुंदरकांड पाठ और हनुमानजी का सिंदूर से विशेष शृंगार किया गया। उधर, हाईकोर्ट स्थित न्यायविद हनुमान मंदिर में दिनभर पूजा–पाठ चलता रहा। शाम को भंडारे में काफी श्रद्धालुओं प्रसाद ग्रहण किया। संवाद

मुट्ठीगंज में प्रसाद वितरित

पहले बड़े मंगल पर मंगलवार को मुट्ठीगंज में बजरंगबली की पूजा के बाद प्रसाद में तहरी वितरित की गई। इस दौरान पार्षद नीरज गुप्ता व भाजपा प्रवक्ता पवन श्रीवास्तव के अलावा विहिप नेता विनोद सोनकर, गौरी आहुजा, निखिल केसरवानी, विशाल अग्रहरी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।

वहीं सिविल लाइंस स्थित तुलसियानी प्लाजा में मंगलवार को विशाल भंडारा व प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी, पार्षद पंकज जायसवाल विश्वास रावत ने किया। देर शाम तर चल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

व्यापार मंडल अध्यक्ष नीरज जायसवाल व महिला अध्यक्ष स्वाती निरखी ने बताया कि हर बड़े मंगलवार को सुंदरकांड, भंडारा और शरबत सेवा की जाएगी। कार्यक्रम में पार्षद पंकज जायसवाल, पंकज भार्गव, रौनक गुप्ता, मधुर मेहरोत्रा, सुबोध अग्रवाल, आकाश सोनी सहित अन्य श्रद्धालु शामिल रहे।

आईटी पार्क के लिए पीडीए झलवा में नगर निगम को उपलब्ध कराएगा 20 एकड़ भूमि

प्रयागराज। आईटी पार्क के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण नगर निगम को झलवा में 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगा। मंगलवार को प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद के साथ नगर निगम स्मार्ट सिटी में हुई बैठक के दौरान पीडीए उपाध्यक्ष ऋषि राज ने महापौर गणेश केसरवानी को जून तक भूमि उपलब्ध कराने की बात कही। इन दिनों एयरपोर्ट रोड के पास पीडीए एयरो सिटी विकसित कर रहा है। इसी एयरो सिटी में 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में महापौर ने पैदल राम सेतु निर्माण, चौक क्षेत्र में अंडरग्राउंड पार्किंग व मीना बाजार का विकास, टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 10 एकड़ भूमि का आवंटन की माग उठाई। इसके अलावा वर्किंग वूमेन हॉस्टल की स्थापना व हेरिटेज मोहल्ला दारागंज, लोकनाथ व मालवीय नगर के विकास योजना प्रमुख रूप से बैठक में शामिल रहे। महापौर ने चौक क्षेत्र की यातायात समस्या को रेखांकित करते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग को अत्यंत आवश्यक बताया। वहीं मीना बाजार के विकास से स्थानीय व्यापार को नई गति मिलेगी।

बैठक में सीएम ग्रिड के तहत सड़कों के निर्माण, टाउन वेंडिग, पार्कों के सौंदर्यीकरण सहित कई अन्य योजनाओं पर चर्चा हुई। इस दौरान नगर आयुक्त साई तेजा, पीडीए सचिव अजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त अरविंद राय, राजीव शुक्ला व सहायक नगर आयुक्त दीप शिखा सहित अन्य मौजूद रहे।

प्रमुख सचिव ने अर्बन चौलेंज के तहत विकास कार्यों के लिए मांगे प्रस्ताव

नगर निगम में बैठक के दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषि राज को अर्बन चौलेंज फंड के तहत विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव शीघ्र ही शासन को भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज में रीडेवपलमेंट से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अर्बन चौलेंज योजना को स्मार्ट सिटी की जगह लाया गया है। इस योजना के तहत विकास कार्यों के लिए 25 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार व 25 फीसदी धनराशि नगर निगम या प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपने मद से देगा और बाकी 50 फीसदी धनराशि का इंतजाम बैंक से लोन लेकर या पीपीपी मॉडल के माध्यम से निजी एजेंसियों को जोड़कर करना होगा।

ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों के दम पर किया दुश्मनों का सफाया: संजय सेठ

प्रयागराज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंगलवार को प्रयागराज में आयोजित नॉर्थ टेक सिम्पोजियम–2026 में हुंकार भरते हुए कहा कि भारत की सैन्य शक्ति अब देश की रक्षा फैक्टरियों में गढ़ी जा रही है। उन्होंने पिछले वर्ष हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख करते हुए इसे भारतीय सेना के अदम्य साहस और स्वदेशी तकनीक का बेजोड़ संगम बताया।

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन में जिस तरह से मेड–इन–इंडिया हथियारों ने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, वह इस बात का प्रमाण है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब केवल एक संकल्प नहीं, बल्कि हकीकत बन चुकी है।

न्यू कैंट में आयोजित इस तीन दिवसीय तकनीकी समागम के दूसरे दिन रक्षा राज्य मंत्री ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई को विकसित भारत के लक्ष्य का सारथी बताया। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमी और छोटे उद्योग हमारे युग के विश्वकर्मा हैं, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतार रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नया भारत न तो किसी को डराता है और न ही अपनी संप्रभुता पर आंच आने देता है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और तकनीक के मामले में दुनिया से दो कदम आगे रहें। इस अवसर पर मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने सेना और उद्योग जगत के बीच गहरे तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से ही हमें सामरिक स्वायत्तता और तकनीकी संप्रभुता हासिल होगी। कार्यक्रम में उत्तरी कमान के जीओसी–इन–सी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और सिड्म के अध्यक्ष अरुण टी रामचंद्रानी सहित सेना के कई आला अधिकारी और उद्योग जगत के दिग्गज मौजूद रहे।

प्रदर्शनी में स्वदेशी तकनीक का जलवा

रक्षा राज्य मंत्री ने न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम परिसर में लगी प्रदर्शनी को देखा। यहां लगे 284 स्टालों पर भारतीय रक्षा निर्माताओं ने अपनी अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने विशेष रूप से स्वदेशी ड्रोन, काउंटर–यूएवी सिस्टम, सर्विलांस उपकरण और ऑल–टेरेन वाहनों को देखा।

आदेश को भ्रामक बताने पर संभल के डीआईओएस पर एक लाख हर्जाना

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश को भ्रामक बता याचियों का दावा अस्वीकार करने पर संभल के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। उन्हें हर्जाने की रकम निजी वेतन से एक हफ्ते में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची को अधिकारी की हठधर्मिता और आदेश की गलत व्याख्या के कारण दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसके लिए हर्जाना लगाया जाना जरूरी है। कोर्ट ने प्रबंध समिति के खिलाफ पारित डीआईओएस के आदेश को रद्द कर नए सिरे से फैसला लेने का निर्देश दिया है।

मामले के मुताबिक, 19 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर डीआईओएस को निर्देश दिया था कि वह डॉ. दीपक भाटिया व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित पूर्व फैसलों के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति और तदर्थ प्रधानाचार्य के कार्यभार पर नया निर्णय लें। इस दौरान चयनित शिक्षक को तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने की अनुमति भी दी थी, लेकिन डीआईओएस ने कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय अपने आदेश में यह लिख दिया कि 19 जनवरी का आदेश न्यायालय को गुमराह करके प्राप्त किया गया है।

इस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जब राज्य सरकार ने उस आदेश को चुनौती नहीं दी थी तो डीआईओएस को ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने न केवल आदेश की गलत व्याख्या की, बल्कि याचिकाकर्ता को दोबारा अदालत आने पर मजबूर किया जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

हर्जाना लगाने के साथ कोर्ट ने डीआईओएस को अंतिम अवसर देते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए मामले को इस निर्देश के साथ दोबारा उनके पास भेजा दिया कि डीआईओएस 19 जनवरी के आदेश का अक्षरशः पालन करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्व–वित्तपोषित योजना के तहत नियुक्तियां नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

मासूम से दुष्कर्म और हत्या का दोषी फांसी के खिलाफ पहुंचा हाईकोर्ट

प्रयागराज। आठ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या में फांसी की सजा पाए युवक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला की खंडपीठ ने पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 29 मई को तय की है।

मामला प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र का है। तीन अक्तूबर 2024 को पीड़िता अपने बीमार पिता के इंजेक्शन की बची हुई दवा मेडिकल स्टोर पर रखने गई थी। इसके बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। अगले दिन चार अक्तूबर को उसका शव गांव के ही धान के खेत में मिला। पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक साक्ष्यों से पुष्टि हुई कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की गई।

राधे कप महिला वॉलीबाल प्रतियोगिता 10 मई से

प्रयागराज। राधे कप जिला स्तरीय महिला वॉलीबाल प्रतियोगिता आगामी 10 व 11 मई 2026 स्थानीय सिविल लाइंस स्थित प्रधान डाकघर के क्रीड़ा परिसर में संपन्न होगी। उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्रतियोगिता के आयोजन सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि वॉलीबाल खेल के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं जिला वॉलीबाल संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव के पद पर रह चुके स्व.राधेश्याम श्रीवास्तव की स्मृति में प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट वॉलीबाल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित की जा रही है। जिसमें भाग लेने की इक्छुक टीमें आयोजक मंडल के सदस्य राजेश वर्मा, विजया सिंह एवं आर.पी.शुक्ला से संपर्क करके अपने टीम की भागीदारी सुनिश्चित करा सकती है।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन पर मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट की अल्ट्रासाउंड मशीन सील

मथुरा। जनपद में अवैध लिंग जांच पर सख्ती जारी रखते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी एवं जनपदीय समुचित प्राधिकारी के निर्देश पर पीसीपीएनडीटी समिति द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट की अल्ट्रासाउंड/ईको मशीन को सील कर दिया गया। बुधवार को उप जिलाधिकारी सदर आदेश कुमार, पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. चित्रेश कुमार निर्मल एवं समिति सदस्य उत्तम चौधरी की टीम ने संस्थान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया। उल्लंघन की पुष्टि होने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड/ईको मशीन को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रूण लिंग जांच जैसे अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

युवक पर लाठी-रॉड से हमला,डेढ़ दर्जन अज्ञात समेत 18 पर मारपीट का केस दर्ज

लखनऊ (संवाददाता)। बंथरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर हमला हुआ। निवाजीखेड़ा गांव में सुदेश रावत को लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित सुदेश रावत ने बताया कि यह घटना 5 मई 2026 की रात करीब 9 बजे हुई। वह निवाजीखेड़ा गांव जा रहा था, तभी अमन, आकाश, विकास और 15 अन्य अज्ञात लोगों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और विरोध करने पर लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमलावरों ने सुदेश के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और उसके बाएं पैर पर भी गंभीर चोटें पहुंचाईं। पीड़ित ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। बंथरा पुलिस ने सुदेश रावत की तहरीर के आधार पर अमन, आकाश, विकास और 15 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

500 छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की मिली ट्रेनिंग,एनसीसी कैडेट्स को किया गया जागरूक

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ में एनसीसी छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। ग्यारहवीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल में रेड ब्रिगेड ने एनसीसी लखनऊ ग्रुप के कैडेटों के लिए प्रशिक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था 'महिला उत्पीड़न और छेड़छाड़ के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने का साहस', जिसमें बड़ी संख्या में कैडेट्स और एनसीसी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल गौरव गौतम शामिल हुए। संगोष्ठी का संचालन रेड ब्रिगेड की अध्यक्षा उषा विश्वकर्मा ने किया। उन्होंने अपने सशक्त वक्तव्यों और व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से कैडेटों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उषा विश्वकर्मा ने बताया कि महिलाएं किस तरह आत्मरक्षा कर सकती हैं। किसी भी आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित कैसे रखें, सुनसान जगह पर खतरे की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें और अपने रक्षा कैसे करें। कार्यक्रम के दौरान लगभग 500 एनसीसी कैडेटों को महिला सुरक्षा, आत्मविश्वास, और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के विषय में जागरूक किया गया। उषा विश्वकर्मा ने उदाहरणों और लाइव डेमो के जरिए बताया कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में साहस और समझदारी से काम लिया जा सकता है।

योगी सरकार में बदली शिक्षामित्रों की तस्वीर

प्रशिक्षण, डिजिटलाइजेशन और स्पष्ट जिम्मेदारी से बदली कार्य-संस्कृति

लखनऊ (संवाददाता)। योगी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से शिक्षामित्रों को तकनीकी, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाया। उन्हें सिर्फ सहयोगी की भूमिका से बाहर निकाला और शिक्षा व्यवस्था का सक्षम एवं जिम्मेदार अंग बनाया। लगातार प्रशिक्षण, डिजिटल साधनों से जोड़ने और जिम्मेदारी तय करने के बाद शिक्षामित्रों ने खुद को इस नई भूमिका के अनुरूप साबित किया, तब सरकार ने उन्हें मानदेय बढ़ोतरी का लाभ देकर उनके योगदान को सम्मानित किया। सरकार ने सुधार को जमीन पर उतारते हुए शिक्षामित्रों की स्थिति और भूमिका दोनों को मजबूत किया है।

राष्ट्रीय कवि संगम, कर्नाटक प्रान्त की मासिक गोष्ठी सम्पन्न

राष्ट्रीय महामंत्री पधारे एवं प्रान्त कार्यकारिणी ने किया संयोजन

शहर समता - कुँ० प्रवल प्रताप सिंह राणा 'प्रवल'

बेंगलुरु। राष्ट्रीय कवि संगम, कर्नाटक प्रान्त के तत्वावधान में अप्रैल 2026 माह की मासिक गोष्ठी का आयोजन रविवार 19 अप्रैल, 2026 को हुआ, गोष्ठी सायं 6.00 बजे से प्रारम्भ हुई। गोष्ठी का संयोजन कुँ० प्रवल प्रताप सिंह राणा 'प्रवल' व अजय यादव 'आवारा' ने किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेश कुमार शर्मा जी ने भाग लिया,गोष्ठी का संचालन टी वी शो सतमोला कवियों की चौपाल के मानद निदेशक और राष्ट्रीय कवि संगम कर्नाटक प्रान्त के उपाध्यक्ष कुँ० प्रवल प्रताप सिंह राणा श्प्रवलश ने किया।

कवि गोष्ठी में सदस्य कवि कवयित्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

मुख्य अतिथि द्वारा सांकेतिक दीप प्रज्वलन के आवाहन पर संचालक ने स्वयं माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया और आचार्य विनीता लवानियाँ द्वारा विनीत भाव से की गई सरस्वती वंदना के उपरांत सभी रचनाकारों ने अपनी प्रतिनिधि रचनाएँ प्रस्तुत कीं , गोष्ठी में महेश कुमार शर्मा, कुँ० प्रवल प्रताप सिंह राणा श्प्रवलश, अजय यादव श्आवाराश, आचार्य विनीता लवानियाँ, अरुणा राणा, पद्मा श्रीनिवासन, लता चौहान, एड अंजू भारती, राधेश्याम यादव सुदर्शन, प्रेम प्रकाश पांडेय, ज्योति वैदेही सोनी और विक्रांत गुप्ता ने काव्य पाठ किया।

गोष्ठी के अंत मे मुख्य अतिथि महेश कुमार शर्मा जी ने सफल गोष्ठी के आयोजन की बधाई दी और सभी का उत्साहवर्धन किया और प्रतिमाह आयोजित करने के लिए पूर्ण समर्थन देने का वायदा किया , मुख्य अतिथि महोदय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश मित्तल द्वारा अनुमोदित, कर्नाटक प्रान्त की कार्यकारिणी घोषित की जिसमें श्री अजय यादव श्आवाराश को अध्यक्ष, कुँ० प्रवल प्रताप सिंह राणा श्प्रवलश को उपाध्यक्ष और आचार्य विनीता लवानियाँ को सचिव मनोनीत किया गया है। श्री शर्मा ने संगठन के कार्य और अधिक ऊर्जा से करने के लिये प्रेरित किया और आज आयोजित गोष्ठी के लिए आयोजको को बधाई भी दी। उनके आह्वान पर संयोजकगण ने प्रतिमाह गोष्ठी आयोजित करने के संकल्प को दोहराया, राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेश कुमार शर्मा ने अन्य राज्यो में भी इसी प्रकार गोष्ठियां आयोजित करने में सहयोग करने हेतु श्री राणा जी से आव्हान किया और भविष्य के कार्यक्रमों के लिए मंगलकामना की। परस्पर बधाई और अगले माह गोष्ठी आयोजित करने के संकल्प के साथ ही गोष्ठी का समापन हुआ।

श्री मंगला प्रसादी सेवा मंडल रजि. मथुरा द्वारा आम मनोरथ फूल बंगला एवं भजन संध्या 31 को

मथुरा। श्री द्वारिकाधीश मंगला प्रसादी सेवा मंडल रजि. मथुरा द्वारा द्वारिकाधीश मंदिर प्रांगण में आम-मनोरथ एवं फूल बंगला और भजन संध्या का आयोजन 31 मई रविवार को सायं 5 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम में द्वारकाधीश मंदिर मे फलों का बगीचा व भव्य फूल बंगला सजेगा उसके उपरांत यमुना पैलेस मे ब्रज की सुप्रसिद्ध भजन गायिका रिया बृजवासी द्वारा भक्तजन भजन संध्या का आनंद लेंगे व भोजन प्रसादी के साथ समापन किया जायेगा। मंडल के एडमिन सौरभ वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन श्री द्वारकाधीश मंगला प्रसादी सेवा मंडल रजि. मथुरा के स्थापना पर्व के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है सायं 5 बजे ठा द्वारकाधीश मंदिर में फूल बंगला एवं आम मनोरथ के दर्शन होंगे। इस मंडल द्वारा श्री द्वारकाधीश मंदिर मे मंगला दर्शन के समय 2 कि. प्रसादी का प्रतिदिन वितरण किया जाता है, सभी त्योहारों और उत्सवो के अवसर पर ग्रुप के द्वारा विभिन्न प्रसादी व भण्डारों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।

ग्रुप के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अनाथ एवं असहाय बच्चों को भी विभिन्न सामग्री व निर्धन बच्चों की स्कूल फीस ग्रुप के द्वारा जमा करायी जाती है।कार्यक्रम की तैयारियों के लिए ग्रुप के द्वारा एक टीम गठित की गयी है, जिसमें लवकेश गोला,समाज सेवी सौरभ वर्मा, दीपक अग्रवाल, डॉ मीनाक्षी सिंह, भूपेन्द्र गौतम, महेश खण्डेलवाल, संदीप अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, रामविलास द्विवेदी, विष्णु शर्मा, अंशुल गौतम , उमेश भदौरिया, संजय सोनी आदि मेम्बरों को मैन जिम्मेदारी दी गई है। वही मंडल के ग्रुप एडमिन टीम ने सभी दर्शनार्थियों से निवेदन किया है द्वारिकाधीश मंदिर में आकर आम मनोरथ फूल बंगला के दर्शन कर पुण्य लाभ उठाए।

कभी भी हो सकता योगी कैबिनेट विस्तार

केंद्र की हरी झंडी का इंतजार, भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे आगे

लखनऊ (संवाददाता)। वेस्ट बंगाल और असम चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान की नजर यूपी पर है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी है। दिल्ली की हरी झंडी मिलते ही सात मई के बाद मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मंत्री बनने की दौड़ में कुछ नाम आगे दिख रहे हैं।कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी तय है। पीडीए की काट में पिछड़ों को वरीयता भी मिलने वाली है। दलित प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। कुछ लोग संगठन से सरकार में शिफ्ट होंगे तो कुछ कैबिनेट से संगठन में भी भेजे जा सकते हैं। बीजेपी हमेशा कुछ नया और अप्रत्याशित करने के लिए जानी जाती है, जाहिर है कि कोई चौकाने वाला नाम भी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। कुछ के हटने तो कइयों का घटने की चर्चा है। संघ की शरण में भी कई मंत्री हैं। पार्टी का फोकस सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण पर है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मशक्कत हो चुकी है। सूची लगभग फाइनल है। पार्टी नेतृत्व का मंत्रिमंडल पर फोकस है। सात को बिहार में विस्तार और नौ को बंगाल में गठन की चर्चाओं के बीच यूपी की तारीख तय होने का इंतजार है। सूत्रों की मानें तो पार्टी ने यूपी को लेकर भी काफी कुछ तय कर लिया है। पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को लेकर मुहिम चला रही है। ऐसे में टीम योगी में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की तैयारी है। फतेहपुर से तीन बार की विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे महिला के साथ ही दलित पासी कोटा पूरा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में पासी मतदाताओं की नाराजगी देखी गई थी। नाम महमूदाबाद की विधायक आशा मौर्य का भी है। अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर की लॉटरी लग सकती है। अनूप प्रधान वाल्मीकि के लोकसभा जाने के बाद मंत्रिमंडल में कोई वाल्मीकि चेहरा नहीं है। कांग्रेसी गढ़ रायबरेली से मनोज पांडेय का नाम भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। पांडे राज्यभा चुनाव के दौरान सपा छोड़ भाजपा में आए थे। ब्राह्मण कोटे में नाम श्रीकांत शर्मा का भी है।उनका भी कद बढ़ना तय माना जा रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। ओबीसी कोटे में ही एक नाम हंसराज विश्वकर्मा का भी चर्चा में है। वे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। वाराणसी से पहले ही कई चेहरे टीम योगी का हिस्सा हैं। क्षत्रिय कोटे से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह और संतोष सिंह के नाम रेस में हैं। कुछ मंत्रियों को हटाने और कुछ के विभाग बदले जाने को लेकर मंथन हो रहा है। कुछ का श्वजनश कम किया जा सकता है। कई मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। कुछ संघ की शरण में जा पहुंचे हैं। कुछ उम्रदराज मंत्रियों की बेचैनी बढ़ी हुई है।

जनता दर्शन में सीएम योगी ने लोगों को दिया भरोसा, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज कराने में भरपूर मदद करेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 फरियादियों से मुलाकात की और उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं।

धूप भी लगे परायी

(छप्पय)

सुनो! कह रहे वृक्ष धरा के हम ही, हैं धन।
हमसे है संसार हमीं से जंगल-उपवन।
हरियाली का रंग और खुशबू फूलों की।
आकर्षण का केन्द्र बने सारे पौधों की।
जंगल सहते ताप को धरती को देकर नमी।
समझो इस विज्ञान को होगी जब इनकी कमी।।

सड़कों का विस्तार पेड़ की शामत आयी।
सिसक रही है भूमि धूप भी लगे परायी।
आँधी-पानी, ताप जगत से नाता जोड़ें।
बादल का हर रूप अहं मानव का तोड़ें।
रेत उड़ रही खेत में, हरियाली ख़ामोश है।
गमलों में बरगद दिखे ग़ज़ब विकासी दौर है।।

डॉ. प्रदीप चित्रांशी
लूकरगंज, प्रयागराज

सीएम ने काशी विश्वनाथ एवं बाबा कालभैरव का किया दर्शन-पूजन

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वाराणसी पहुंचे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं बाबा कालभैरव मंदिर जाकर दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री बड़ा लालपुर स्थित चांदमारी निवासी राजीव कृष्ण के आवास पर गए। जहां आयोजित शादी के अवसर पर उन्होंने परिवार जनों को बधाई दी। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ दयाशंकर मिश्र श्दयालुश, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉ अवधेश सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

ताकत के बल पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में नकली विजय प्राप्त की-भाकपा

लखनऊ (संवाददाता)। केन्द्रीय बलों की छत्र छाया में चुनाव आयोग के मूक समर्थन से संघियों के बल पर पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा सरकार पर कब्जा किया है। यह बात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य डॉ रामचन्द्र सरस ने बाराबंकी में बयान जारी करते हुए कहा कि एसआईआर से चुनाव धांधली की शुरुआत हुई और मतगणना तक ताकत के बल नकली विजय प्राप्त किया गया है। हद यहां तक हो गई है कि ढाई लाख केन्द्रीय सशस्त्र बलों के सामने लेनिन की मूर्ति जियागंज में तोड दी गई। जगह-जगह संघी आगजनी तोडफोड़ मारपीट कर रहे हैं। केन्द्रीय बल खामोश है।न्याय पालिका खामोश है।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश भर में जनजागरण और आंदोलन करेगी।

चौधरी अजित सिंह किसानों के सच्चे हितैषी और उनकी आवाज थे-रामाशीष

लखनऊ (संवाददाता)। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश मुख्यालय पर किसानों के प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजित सिंह की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने कहा कि चौधरी अजित सिंह किसानों के सच्चे हितैषी और उनकी आवाज थे। उन्होंने हमेशा किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके सिद्धांत, विचार आज भी हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे चौधरी साहब के बताए मार्ग पर चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का कार्य करें।

उत्तर मध्य रेलवे

निविदा सूचना सं.: 16202/2027 | ई-निविदा सूचना | दिनांक: 04.05.2026

मण्डल रेल प्रबन्धक / इंजीनियरिंग / उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित निर्धारित कार्य के लिये ई-निविदाएँ प्रपत्र पर दिनांक 28.05.2026 को 13:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	निविदा नं.	अनुमानित मूल्य (रु.)	बयाने की रकम (रु.)
1	54	1,65,00,000.00	3,30,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल इन्जीनियर/मुख्यालय/द्वितीय/कानपुर के अधीन वरि0 खण्ड इंजी/कार्य/स्टेशन/कानपुर के सेक्शन में कार्यावधि 30.06.2027 हेतु जोन सेन्ट्रल में वार्षिक सिविल मरम्मत/रखरखाव एवं छोटे नये कार्यों का कार्य।			
2	55	1,50,00,000.00	3,00,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल इन्जीनियर/मुख्यालय/द्वितीय/कानपुर के अधीन वरि0 खण्ड इंजी/कार्य/मुख्यालय/कानपुर के सेक्शन में कार्यावधि 30.06.2027 हेतु जोन मुख्यालय में वार्षिक सिविल मरम्मत/रखरखाव एवं छोटे नये कार्यों का कार्य।			
3	56	65,00,000.00	1,30,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल इन्जीनियर/मुख्यालय/द्वितीय/कानपुर के अधीन वरि0 खण्ड इंजी/कार्य/मु0/कानपुर के सेक्शन में कार्यावधि 30.06.2027 हेतु जोन सी.एन.बी.एन सीटा हॉस्टल, स्कूल, ओ.आर.एच एवं सहायक मण्डल अभियन्ता ऑफिस में वार्षिक सिविल मरम्मत/रखरखाव एवं छोटे नये कार्यों का कार्य।			
4	57	1,50,00,000.00	3,00,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल इन्जीनियर/मुख्यालय/द्वितीय/कानपुर के अधीन वरि0 खण्ड इंजी/कार्य/सी.पी.सी./कानपुर के सेक्शन में कार्यावधि 30.06.2027 हेतु जोन नार्थ में वार्षिक सिविल मरम्मत/रखरखाव एवं छोटे नये कार्यों का कार्य।			
5	58	1,45,00,000.00	2,90,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल इन्जीनियर/मुख्यालय/द्वितीय/कानपुर के अधीन वरि0 खण्ड इंजी/कार्य/जुही/कानपुर के सेक्शन में कार्यावधि 30.06.2027 हेतु जोन साउथ एवं सीटा में वार्षिक सिविल मरम्मत/रखरखाव एवं छोटे नये कार्यों का कार्य।			
6	59	1,50,00,000.00	3,00,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल इन्जीनियर/मुख्यालय/द्वितीय/कानपुर के अधीन वरि0 खण्ड इंजी/कार्य/स्पेशल-1/कानपुर के सेक्शन में कार्यावधि 30.06.2027 हेतु जोन वेस्ट में वार्षिक सिविल मरम्मत/रखरखाव एवं छोटे नये कार्यों का कार्य।			
7	60	1,45,00,000.00	2,90,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल इन्जीनियर/मुख्यालय/द्वितीय/कानपुर के अधीन वरि0 खण्ड इंजी/कार्य/सी.पी.ए./कानपुर के सेक्शन में कार्यावधि 30.06.2027 हेतु जोन कानपुर अनवरगंज में वार्षिक सिविल मरम्मत/रखरखाव एवं छोटे नये कार्यों का कार्य।			
8	61	95,00,000.00	1,90,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल इन्जीनियर/मुख्यालय/द्वितीय/कानपुर के अधीन वरि0 खण्ड इंजी/कार्य/जुही/कानपुर के सेक्शन में कार्यावधि 30.06.2027 हेतु जोन इलेक्ट्रिक लोको शेड, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर एवं ट्रैक्शन मोटर शाप (टी.एम.एस.) में वार्षिक सिविल मरम्मत/रखरखाव एवं छोटे नये कार्यों का कार्य।			
9	62	75,00,000.00	1,50,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल अभियन्ता/मुख्यालय/द्वितीय/कानपुर के अन्तर्गत 30.06.2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक बागवानी के रखरखाव का कार्य।			
10	63	1,40,00,000.00	2,80,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल अभियन्ता/लाइन/कानपुर के अधीन गोविन्दपुरी (छोड़कर) से किमी. 1069 तक कार्यावधि 30.06.2027 हेतु जोन में वार्षिक सिविल मरम्मत/रखरखाव एवं छोटे नये कार्यों का कार्य।			
11	64	1,00,00,000.00	2,00,000.00
कार्यों का विवरण: सहायक मण्डल अभियन्ता/लाइन/कानपुर के अधीन कार्यावधि 30.06.2027 हेतु पीo वेo जोन का कार्य।			
कार्य समापन की अवधि: 12 माह		निविदा खुलने की तिथि: 28.05.2026	

इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अन्तर्गत सिमिलर कार्य: क्र.सं. 1 से 8 व 10 के लिये- कोई सिविल इंजीनियरिंग कार्य, क्र.सं. 9 के लिये- कोई बागवानी कार्य एवं क्र.सं. 11 के लिये- कोई पी.वे. कार्य।

नोट: 1. ऑन लाइन निविदा दिनांक 28.05.2026 को 13:30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। 2. उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.ireps.gov.in पर समय 13:30 बजे टेण्डर खुलने की तिथि 28.05.2026 तक उपलब्ध है। 997/26 (ADM)

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @CPRONCR

सम्पादकीय.....

किराये की संतान

जीवन की सांझ में बुजुर्गों को अपनों के पास न होने की टीस सालती है। कई बुजुर्गों के बच्चे विदेशों में अपना भविष्य तलाशने गए तो फिर लौटकर नहीं आये। जीवनभर की जमा–पूंजी से बनाये गए बड़े–बड़े घरों में वे सिर्फ दीवारें ताकते हैं। बच्चों के पास जाते भी हैं तो वहां रात–दिन काम में जुटे बच्चों के साथ रहना उन्हें रास नहीं आता। आत्मकेंद्रित होती पीढ़ी भी भारत में रहने वाले माता–पिता की सुध लेने लौटकर तक नहीं आती। ऐसे में साधन–संपन्न बुजुर्ग को कई बड़े शहरों में ऐसी कंपनियां किराये की सतानें उपलब्ध कराती हैं। ये किराये की संतानें बुजुर्गों के साथ सैर पर जाते हैं, लूडो आदि खेल खेलते हैं और उनका एकाकीपन दूर करते हैं। यद्यपि यह समस्या का अंतिम समाधान तो नहीं है लेकिन कुछ समय के लिए वे राहत महसूस करते हैं। दरअसल, बुजुर्गों के जीवन में अंदर से खालीपन इतना बढ़ गया है जिसे भरने के लिए वे किराये की संतानों की ओर उन्मुख होते हैं। कई कंपनियां बुजुर्गों को केयर का पैकेज देती हैं। वे ऐसे अटेंडेंट उपलब्ध कराती हैं जो बुजुर्गों के साथ बैठकर टीवी देखते हैं, ताश खेलते हैं, दिन–भर बातें करते हैं। कंपनियों की यह सुविधा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गई बल्कि गांवों तक लोग इन्हें अनुबंधित कर रहे हैं। हालांकि, खून के रिश्तों का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन तात्कालिक तौर पर वे इनकी उपस्थिति में कुछ सुकून हासिल कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे दौर में जब उम्र–दराज लोगों के आय के स्रोत सिमटने लगते हैं और शरीर भी साथ नहीं देता तो बहुत से लोगों के सामने किराये की संतान का बोझ उठाना भी मुश्किल होता है। खासकर निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए जिनकी पेंशन भी मुट्ठी में सिमट जाती है। विकसित देशों में सेवानिवृत्त लोगों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं लागू रहती हैं। वे अपनी नौकरी के दौरान पर्याप्त आयकर देते हैं। फिर सेवानिवृत्ति पर सरकारें उनकी देखभाल व मेडिकल सुविधाओं का दायित्व निभाती हैं। भारत में कथित लोककल्याणकारी सरकारें भरपूर आयकर वसूलने के बाद भी जिंदगी की सांझ में बुजुर्गों को उनके हाल पर छोड़ देती है। अपने भी गांठ का धन मजबूत होने पर ही अपने साथ निभाते हैं। ऐसे में बुजुर्गों व वृद्धों का जीवन अवसादमय हो जाता है। लगातार महंगी होती चिकित्सा सुविधाएं और आय के स्रोतों का संकुचन उन्हें भविष्य के भय से भर देता है। वास्तव में बुजुर्गों व वृद्धों को जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हुए इसका मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। शारीरिक सक्रियता, योग, ध्यान, प्राणायाम व सत्संग उनके लिए मददगार होता है। अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा की जाती है कि यदि अनाथ आश्रमों के बच्चों को ओल्ड ऐज होम के बुजुर्गों के साथ रखा जाए तो दोनों की समस्या हल हो सकती है। एक ओर बच्चों को जहां अभिभावक मिल सकते हैं, वहीं बुजुर्गों को बच्चे मिल सकते हैं। गुणवत्ता वाले सुविधा–संपन्न वृद्धाश्रमों को बनाने के लिए सरकार के स्तर पर बड़े प्रयास करने की जरूरत है।

सूचना का अधिकार : नियंत्रित पारदर्शिता की ओर बढ़ता भारत

अरुण कुमार डनायक

केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा रूस से भारत के कच्चे तेल आयात संबंधी विस्तृत जानकारी को सार्वजनिक करने से इनकार को 27 अप्रैल 2026 के हालिया फैसले में बरकरार रखा गया, जो एक बार फिर यह प्रश्न उठाता है कि पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन कहां स्थापित किया जाए। आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(डी)कृजो वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा से जुड़ी ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट देती है जिनसे किसी तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती हैकृऔर धारा 8(1)(ई)कृजो विश्वासगत संबंध में प्राप्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती हैकृका हवाला देते हुए कहा कि कंपनी–वार आयात डेटा में मूल्य निर्धारण, अनुबंध, छूट और व्यापारिक रणनीतियों जैसी संवेदनशील जानकारियां शामिल होती हैं, जिन्हें सरकार विश्वासगत आधार पर प्राप्त करती हैय अतरू इनके प्रकटीकरण को छूट के दायरे में रखा जाना उचित है। इस प्रकार आयोग ने पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के उस निर्णय को सही ठहराया, जिसमें जून 2022 से जून 2025 के बीच रूस से आयातित कच्चे तेल का कंपनी वार और विस्तृत देश वार विवरण देने से मना किया गया था। पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रमुख तकनीकी विश्लेषणात्मक विंग है, जो डेटा संग्रह, विश्लेषण और नीति समर्थन के माध्यम से देश की ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। यह फैसला सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। आवेदक ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, रिलायंस और नायरा एनर्जी के लिए अलग–अलग आंकड़े मांगे थे । हालांकि आयोग ने अपील खारिज कर दी, लेकिन साथ ही पीपीएसी को आरटीआई अधिनियम की धारा 4 और 25(5) के तहत स्वप्रेरित पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। यह रुख आयोग के उस प्रयास को दर्शाता है, जिसमें वह गोपनीयता और सार्वजनिक सूचना के बीच संतुलन साधना चाहता है। फिर भी, विस्तृत आयात डेटा को छूट देते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश देना कुछ हद तक विरोधाभासी प्रतीत होता है। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती रूसी तेल आयात बढ़ाया और 2024–25 में रूस उसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गयाय वैश्विक प्रतिबंधों, मध्य पूर्व तनाव और अमेरिका के दबाव रियायत के बीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करता रहा है। सरकार का तर्क है कि कई देशों में संवेदनशील व्यापारिक डेटा को गोपनीय रखना सामान्य प्रथा है। ऊर्जा आयात अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भू राजनीतिक विषय हैय इसलिए यह जानकारी सार्वजनिक करने से कंपनियों की सौदेबाजी क्षमता कमजोर हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं। गोपनीयता के ऐसे फैसलों से यह प्रश्न भी उठता है कि कहीं सरकार अंतरराष्ट्रीय दबावकृविशेषकर अमेरिका की संभावित नाराजगीकृसे बचने के लिए सूचनाओं के प्रकटीकरण में अतिरिक्त सावधानी तो नहीं बरत रही। यह प्रवृत्ति नई नहीं हैय रक्षा, ऊर्जा और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में डेटा साझा करने में सावधानी बरतना लंबे समय से राज्य की नीति रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सूचना को शक्ति माना जाता है। सरकार के तर्कों के बावजूद पारदर्शिता की कुछ गुंजाइश फिर भी है। तेल बाजार अत्यंत अपारदर्शी है। प्रतिबंधित देश पहचान छिपाने हेतु अक्सर गुप्त जहाजों, ध्वज–परिवर्तन जैसे तरीकों से व्यापार करते हैं । ऐसे में यदि कंपनी या देश–वार डेटा सार्वजनिक न हो, तो तेल के वास्तविक स्रोत, कीमत, संभावित अनियमितताओं तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आकलन कठिन हो जाता है। सस्ते कच्चे तेल का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है । जिससे बाजार पारदर्शिता और देश की विश्वसनीयता दोनों प्रभावित होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत छूट तभी लागू हो सकती है, जब सूचना के खुलासे से वास्तविक और प्रमाणित नुकसान हो तथा सार्वजनिक हित उससे अधिक न हो । सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि सूचना का खुलासा नियम है और गोपनीयता अपवाद । सीआईसी ने अपने निर्णय में ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(2) अलग से परीक्षण नहीं किया है , जो स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि धारा 8(1) के तहत दी गई किसी भी छूट के बावजूद, यदि सूचना के प्रकटीकरण से होने वाला जनहित उसे रोकने से होने वाले संभावित नुकसान से अधिक हो, तो संबंधित प्राधिकरण को वह सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। तेल आयात का डेटा स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित से जुड़ा है, क्योंकि यह ऊर्जा सुरक्षा, मूल्य पारदर्शिता, सस्ते कच्चे तेल का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने और नीति की प्रभावशीलता से सीधे संबंधित है। कंपनी वार जानकारी न होने से यह आकलन कठिन हो जाता है कि आयात का लाभ पूरी तरह उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है या कुछ सौदे महंगे पड़ रहे हैं, जिससे नीति मूल्यांकन सीमित होता है और जवाबदेही कमजोर पड़ती है। यह नियंत्रित पारदर्शिता का मॉडल है, जिसमें आंकड़ों की झलक तो मिलती है, लेकिन असली तस्वीर सूक्ष्म गोपनीयता के पर्दे के पीछे ही रहती सीआईसी का यह रुख संकेत देता है कि हाल के वर्षों में वह पारदर्शिता की तुलना में संवेदनशील सूचनाओं पर अधिक सतर्क और प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों की ओट में सूचना को सीमित रखने की प्रवृत्ति है, जिससे रक्षा सौदों सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में जानकारी रोकी गई है, और इससे पारदर्शिता घटने के साथ–साथ संभावित अनियमितताओं या भ्रष्टाचार की प्रभावी जांच और पहचान की क्षमता भी सीमित होती है, जिससे सूचना के अधिकार की मूल भावनाकृखुलासा नियम और छूट अपवादकृकमजोर पड़ने का खतरा बढ़ता है। आधुनिक ऊर्जा और भू–राजनीतिक परिदृश्य में पूर्ण अपारदर्शिता न तो संभव है और न ही वांछनीय, लेकिन जब गोपनीयता का दायरा लगातार विस्तृत होता जाए और पारदर्शिता अपवाद बन जाए, तो लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का मूल आधार है, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गोपनीयता सार्वजनिक हित तथा नागरिकों के सूचना अधिकार को पीछे न धकेल दे।

भविष्य में ऐसे मामलों में बेहतर संतुलन स्थापित करना आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय हित और पारदर्शिता दोनों सुरक्षित रह सकें। इसके लिए आवश्यक है कि पीपीएसी जैसी संस्थाएं वार्षिक स्तर पर विस्तृत ग्रेनुलर डेटा और त्रैमासिक स्तर पर देश–वार आयात आंकड़े नियमित रूप से प्रकाशित करें, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़े, विशेषज्ञ विश्लेषण संभव हो और सार्वजनिक हित प्रभावी रूप से सुरक्षित रह सके।

केंद्रीय सत्ता की जीत, जनतंत्र की हार!

राजेंद्र शर्मा

विधानसभा चुनाव के मौजूदा चक्र के संबंध में और खासतौर पर प. बंगाल के संबंध में जो बदतरीन आशंकाएं जतायी जा रही थीं, सच साबित होती नजर आती हैं। भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज होने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। बेशक, पूरी तरह से अपनी साख खो चुके चुनाव आयोग ने, मतगणना में अपनी बची–खुची साख की भी बलि चढ़ा दी है। पहले बंगाल की ही बात करें तो मतगणना के दिन दोपहर बाद, साढ़े तीन बजे तक 294 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटों के नतीजे चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जारी किए गए थे। बेशक, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 200 सीटों पर लीड की जानकारी भी आ चुकी थी, लेकिन इस समय तक कुल वोट में से आधे से कुछ ही ज्यादा वोटों की गिनती हो पायी थी। हैरानी की बात नहीं है कि इस चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी, तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग पर मतगणना जान–बूझकर धीमी करने से लेकर, उसकी चुनावी रूप से मजबूत सीटों पर मतगणना की स्थिति छुपाने तक के आरोप लगा रही थी। याद दिला दें कि मतगणना की यह मंथर चाल, सिर्फ प. बंगाल में ही नहीं थी। यह तो जैसे चुनाव आयोग का नया नार्मल ही है। तभी तो पुड्डुचेरी जैसे छोटे राज्य (वास्तव में विधानसभा युक्त केंद्र शासित क्षेत्र) तक में, इस समय तक 25 में से कुल 17 सीटों के ही नतीजे जारी किए जा सके थे और बाकी 8 सीटों पर लीड ही बतायी जा रही थी। बहरहाल, चुनावी मतगणना की विशेष रूप से धीमी रफ्तार, चुनावों के इस चक्र की असली समस्या नहीं है। यह तो एक लक्षण है, चुनाव आयोग के अपनी उस मूल संकल्पना से पूरी तरह से पीछा छुड़ाकर, सत्ताधारी भाजपा के राजनीतिक–चुनावी हितों को आगे बढ़ाने का एक घातक हथियार बन जाने का, जबकि उससे चुनाव प्रक्रिया तथा जनतंत्र के मुख्य हितधारकों के रूप में, सभी राजनीतिक पार्टियों का भरोसा जीतते हुए काम करने वाले, रेफरी की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। चुनाव आयोग की इसी असंवैधानिक भूमिका के विभिन्न पहलू विधानसभा चुनावों के इस चक्र में और सबसे बढ़कर प. बंगाल तथा असम में सामने आए हैं, जिन्हें जीतने की उम्मीद में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस सिलसिले में प. बंगाल में जिस तरह, इस चुनाव की पूर्व–संध्या में मतदाता सूचियों के सघन पुनरीक्षण के नाम पर, लाखों की संख्या में वैध मतदाताओं के नाम काटने की मुहिम चलायी गयी थी, बंगाल के सवा करोड़ से ज्यादा मतदाताओं पर नागरिकता सत्यापन जैसी कसरत थोपी गयी थी और जिस तरह इस सब के चलते, अंततरू 25 लाख मतदाताओं को 2026 के विधानसभा चुनाव में मताधिकार से वंचित ही नहीं कर दिया गया है, आगे के लिए उनकी नागरिकता–मताधिकार पर सवालों का घेरा लगा छोड़ दिया गया है, उसके संबंध में हम पहले भी इस स्तंभ में चर्चा कर चुके हैं। चुनाव आयोग की जिद पर और शीर्ष न्यायपालिका के अनुमोदन से, जिस तरह लाखों लोगों का मताधिकार छीना गया है, उसने जनतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में चुनाव को जिस तरह से विकृत किया है बल्कि एक तरह से चुनाव का अपहरण ही कर लिया है, वह भारतीय जनतंत्र के इतिहास में एक नये रसातल के छुए जाने को दिखाता है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के बंगाल फतेह करने के इस अभियान में जिस तरह पूरे तंत्र को जोता गया था और खासतौर पर शासन के पूरे दमनतंत्र को थोपा गया था, उसने प. बंगाल के ही तीन दशक से ज्यादा पहले के एक चुनाव की याद दिला दी। यह और भी उपयुक्त था कि प. बंगाल में ऐसा पहले भी हो चुका होने की याद, प्रख्यात भारतीय कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के पुर्नप्रकाशन के माध्यम से दिलायी गयी। यह 1972 का विधानसभा चुनाव था। पहले 1967 में सीपीआई (एम) की अग्रणी भूमिका के साथ बनी युक्त फ्रंट सरकार को, तब केंद्र में सत्ता में बैठी कांग्रेस ने गिराया। इसके बाद, 1969 में दोबारा और भी मजबूती से युक्त फ्रंट की सरकार आयी और कांग्रेस ने राज्यपाल का सहारा लेकर उसे भी गिराया। इसके बाद, 1972 का चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने, इसी तरह किसी भी कीमत पर जीतने का फैसला लेकर कराया, जिसमें पुलिस बलों की ताकत का इस हद तक खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग किया गया कि सीपीआई (एम) के नेतृत्व में विपक्ष को पहले मतगणना का और फिर विधानसभा का ही बहिष्कार करना पड़ा था। इसके बाद, कांग्रेस प. बंगाल में सत्ता पर काबिज हो गयी, आज उन्हीं हथकंडों का सहारा लेकर भाजपा बंगाल में सत्ता पर काबिज हो रही है।

और भाजपा भी यह न भूले कि इसके बाद बंगाल की जनता ने पहला मौका मिलते ही, 1977 में कांग्रेस को सत्ता से इस तरह बाहर किया था कि उसके बाद पांच दशक तक कांग्रेस बंगाल में सत्ता के आस–पास भी नहीं फटक सकी। दुर्भाग्य से हम बाकायदा तानाशाही के उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। भाजपा का बंगाल में पहली बार सत्ता में पहुंचना और असम में दोबारा सत्ता पर काबिज होना, इसी का साधन बनने जा रहा है। यह इसलिए है कि यह किसी एक पार्टी के चुनाव में जीत कर सत्ता तक पहुंचने की सामान्य जनतांत्रिक प्रक्रिया का मामला नहीं है। यह जनतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से तोड़–मरोड़कर सत्ता पर काबिज हुए जाने का मामला है। और यह तोड़–मरोड़, सिर्फ बंगाल में पच्चीस लाख से ज्यादा लोगों का मताधिकार छीने जाने या असम में विधानसभा क्षेत्रों के इस तरह पुनर्सीमांकन का ही मामला नहीं है, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया था कि मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली सीटों की संख्या कम से कम कर दी जाए। जाहिर है कि यह सब चुनाव आयोग के माध्यम से ही किया जा रहा था। लेकिन, इसके साथ ही चुनाव आयोग के माध्यम से ही इस चुनाव में यह भी सुनिश्चित किया जा रहा था कि संघ–भाजपा, किसी भी रोक–टोक के डर के बिना कम से कम असम और बंगाल में, कथित घुसपैठियों का झूठा हौवा खड़ाकर, खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक दुहाई पर आधारित चुनाव प्रचार कर सकें और धर्म के आधार पर मतदाताओं का, जाहिर है कि हिंदू मतदाताओं का, ज्यादा से ज्यादा ध्रुवीकरण कर सकें।

रचना सक्सेना के गीत

कहते बहते आँसू मुझसे, कदम मिला चलना।
गीत प्रीत का जब - जब लिखते, हमे पड़ा जलना।।

यह दुनिया है इस दुनिया मे, कौन यहाँ अपना।
मिलते और बिछड़ते राही, टूट गया सपना।।
साथ निभाता कौन दिखे जग, श्वासों का ढलना।
गीत प्रीत का जब - जब लिखते, हमे पड़ा जलना।।

वक्त बीतता जाए पल - पल, सब कुछ स्वप्न लगे।
चिंताओं में उम्र ढले बस, वो ही आज सगे।।
कर्तव्यों से चूक गये तो, हाथ पड़ा मलना।
गीत प्रीत का जब - जब लिखते, हमे पड़ा जलना।।

लक्ष्य साधकर चलते जाना, बस उद्देश्य यही।
हार जीत तो इस जीवन में, अब नैराश्य नही।।
आस प्रीत की हिय जलती तो, भाव नही पलना।
गीत प्रीत का जब जब लिखते, हमें पड़ा जलना।।

रचना सक्सेना
प्रयागराज

चुनावी नतीजों से बनी 2029 की तस्वीर

2014 के कुछ पहले से देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें भाजपा के नरेन्द्र मोदी के बरक्स कांग्रेस के राहुल गांधी को खड़ा किया जाता था। हालांकि 2014 में नरेन्द्र मोदी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और राहुल गांधी एक सांसद से ज्यादा कुछ नहीं थे। फिर भी भाजपा के निशाने पर गांधी परिवार रहता था और इसमें भी राहुल गांधी तो 2004 से ही, जब वे पहली बार सांसद बने थे, तब से भाजपा के निशाने पर रहते थे। दरअसल भाजपा ने 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम छेड़ी थी और उसका यह अनुमान था कि अगर राहुल गांधी को पस्त किया जा सके तो कांग्रेस भी फिर ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगी। 2014 के बाद के जिन चुनावों में कांग्रेस को मात मिलती, उसे भाजपा कांग्रेस मुक्तभारत की तरफ एक और कदम बताती थी। लेकिन धीरे–धीरे उसे समझ आया कि न राहुल गांधी को झुकाना संभव है, न देश को कांग्रेस मुक्त बनाना। इसके बाद भाजपा की रणनीति बदली और उसके निशाने पर आए क्षेत्रीय दल। चाहे विपक्ष के दल हों या एनडीए में भाजपा के अपने सहयोगी दल, किसी को भी बख्शा नहीं गया। 2026 में जो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे इसी रणनीति, इसकी सियासी कहानी का विस्तार कहे जा सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, पुड्डुचेरी, असम और प.बंगाल में 4 मई को आए नतीजे केवल इन राज्यों के लिए नहीं बल्कि समूचे लोकतंत्र के लिए बड़ा संदेश लेकर आए हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक पूरे नतीजे तो घोषित नहीं हुए, लेकिन असम और पुड्डुचेरी में भाजपा की सरकार फिर से बन रही है, प.बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी 15 साल बाद हार रही है, लेकिन भाजपा को बड़ी जीत मिली है, यह ज्यादा बड़ी खबर है। केरल में कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में आ रही है और पहली बार वाम मोर्चा किसी राज्य में सत्ता में नहीं है। वहीं तमिलनाडु में भी डीएमके सत्ता से बाहर हो गई है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके और कांग्रेस गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख पाए। लेकिन यहां की परंपरागत राजनीति की तरह इस बार अन्नाद्रमुक को सत्ता नहीं मिली, बल्कि टीवीके बनाकर राजनीति में पहली बार कदम रखने वाले फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने बड़ी जीत हासिल की है। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी अभिनेता–अभिनेत्रियों का बड़ा कद हासिल करना नया चलन नहीं है। लेकिन फिर भी टीवीके की जीत पर आश्चर्य जताया जा रहा है क्योंकि विजय कभी अपनी रैलियों में अव्यवस्था को लेकर, कभी निजी जीवन के विवादों को लेकर सवालों के घेरे में रहे। यह तो माना जा रहा था कि विजय के कारण वोट बंटेंगे और खासकर स्टालिन को नुकसान होगा, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत वो दर्ज करेंगे। बहरहाल, अब वे किस तरह सत्ता संभालते हैं और क्या कांग्रेस इसका हिस्सा किसी तरह बनती है या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि विजय डीएमके विरोधी तो हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अपना झुकाव वे एकाधिक मौकों पर दिखा चुके हैं। अगर कांग्रेस गठबंधन में उन्हें साथ लेती तो शायद तमिलनाडु में समीकरण बदल सकते थे। बहरहाल, कांग्रेस ने केरल में बड़ी जीत दर्ज की है और उस एलडीएफ को हराया है, जिसे राहुल गांधी कई बार भाजपा का सहयोगी बता चुके हैं। केरल में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा यह तो तय है, बस नाम पर मुहर लगना बाकी है। लेकिन इस जीत में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि उसे यहां खाता खोल चुकी भाजपा को और आगे बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि भाजपा की शुरुआत कम अंकों से भी हो, तब भी अपनी जायज–नाजायज रणनीतियों और तरीकों से वह बड़े अंक जल्द ही ले आती है। प.बंगाल इसी का उदाहरण है। 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद अब नरेन्द्र मोदी के खाते में दो बड़ी सफलताएं जुड़ चुकी हैं। एक तो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना और दूसरा प.बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनाना। इन सफलताओं में ईवीएम धांधली, एसआईआर और चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये का कितना योगदान है, यह अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिए भाजपा का ऐसा प्रदर्शन अब उनके अस्तित्व के लिए ही बड़ी चुनौती बन चुका है। महाराष्ट्र में भाजपा को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सत्ता से बाहर किया तो भाजपा ने पहले शिवसेना और फिर एनसीपी को ही तोड़ दिया। अब इस राज्य में ये क्षेत्रीय दल इतने मजबूत नहीं रह पाएं हैं कि अकेले भाजपा का मुकाबला कर सकें। हरियाणा में भाजपा ने यही खेल जेजेपी के साथ खेला।

सीमा वर्णिका की कलम से

'बक्सा'

बाबूजी का आखिरी वक्त आ गया था। उल्टी साँसें चल रही थी। उन्होंने इशारे से बेटे राजकिशोर को बुलाया। अपनी बनियान की जेब से चाबी देकर बक्से की तरफ जैसे ही इशारा किया.. उनकी गर्दन लुढ़क गई। चारों तरफ रोना पीटना मच गया।

बाबूजी का बक्सा खोला जाना था। सबकी जिज्ञासा बढ़ रही थी कि आखिर ऐसा क्या है इसमें..।

बक्सा खुला.. उसमें यह क्या बाबूजी ने अंतिम संस्कार में प्रयुक्त होने वाली रामनामी ,सफेद नया कपड़ा, गमछा कुर्ता पजामा चित्र लोटा धूपबत्ती गुलाब जल आदि सामान पहले से ही रखा हुआ था साथ ही अन्य संस्कारों के लिए तीस हजार रुपये तथा साथ में एक कागज रखा था जिसमें सभी संस्कारों का क्रमबद्ध वर्णन किया गया था।

राजकिशोर रो पड़ा वह मन ही मन सोच ही रहा था कैसे व्यवस्था करें बाबू जी के अंतिम संस्कार की ।

बाबूजी उसे इस जिम्मेदारी से भी निवृत्त कर गए थे।

सीमा वर्णिका,
कानपुर

इम्तियाज अली की फिल्म से टकराएगी कंगना अभिनीत भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत बीते कुछ दिनों से फिल्मों से ज्यादा राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन अब उनके फैंस का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। कंगना रनौत की आने वाली फिल्म का नाम 'भारत भाग्य विधाता' है। मेकर्स ने इसका पोस्टर जारी कर रिलीज डेट का खुलासा किया है। पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा– 'एक साधारण लोगों की असाधारण कहानी! वो रात, जब इंसानियत डर से भी बड़ी बनकर सामने आई। जब जिम्मेदारी ने बलिदान का रूप लिया, जब एकता ने कर्तव्य निभाया और जब हिम्मत ने कई जिंदगियां बचाईं। भारत के असली हीरोज की अनकही कहानी।' बता दें कि फिल्म में भारत के उन हीरोज की कहानी बताएगी, जो अनसुनी है। बता दें कि फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में नजर आएंगी। इसे मणिकर्णिका फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। इसके लेखक और निर्दशक मनोज तापड़िया हैं। 'भारत भाग्य विधाता' फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फैंस कंगना की वापस फिल्मों में वापसी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला इम्तियाज अली की आगामी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से होगा। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित 'मैं वापस आऊंगा' एक लव स्टोरी है। 'मैं वापस आऊंगा' भी 12 जून को रिलीज होगी, जिसमें दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ और वेदांग रैना प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।

> भारत के असली हीरोज की अनकही कहानी।' बता दें कि फिल्म में भारत के उन हीरोज की कहानी बताएगी, जो अनसुनी है। बता दें कि फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में नजर आएंगी। इसे मणिकर्णिका फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है।

ब्लेक लाइवली और जस्टिन बाल्डोनी के बीच सेटेलमेंट! क्या खत्म हुई को-स्टार्स के बीच कानूनी लड़ाई ?

अगस्त 2024 में हॉलीवुड एक्ट्रेस ब्लेक लाइवली ने साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म इट एंड्स विद अस के को–स्टार और डायरेक्टर जस्टिन बाल्डोनी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही यह विवाद दुनियाभर में चर्चा में रहा। हालांकि, बीते 4 मई को दोनों कलाकारों ने इस मामले पर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया है। बीते दिनों ब्लेक और जस्टिन के बीच चल रहे इस कानूनी विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच अब समझौता हो चुका है। इस समझौते में किसी तरह का कोई वित्तीय मुआवजा नहीं दिया गया है। हालांकि, कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह भी कहा है कि अगर कोई इस समय गोपनीय समझौते की शर्तों की पुष्टि करता है तो वह गुमराह कर रहा है। इस गोपनीय समझौते के बारे में अधिक जानकारी आने वाले दिनों में अदालत के रिकॉर्ड में होगी। मामले में पिछले महीने ही कोर्ट ने लाइवली के कई दावे किए जिनमें यौन उत्पीड़न का दावा भी शामिल था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। ब्लेक लाइवली ने अदालत में यौन उत्पीड़न के आलावा तीन और दावे पेश किए थे। मगर इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने अपने तीनों दावे वापस ले लिए। इनमें से कुछ दावे उन्होंने बाल्डोनी की सह–स्थापित प्रोडक्शन कंपनी वेफेयर स्टूडियोज और उसके प्रचारकों की टीम के खिलाफ किए थे। एक्ट्रेस ब्लेक लाइवली और जस्टिन बाल्डोनी के बीच की यह कानूनी लड़ाई लगभग दो साल से चल रही है। अभिनेत्री ने अपने को–स्टार और डायरेक्टर पर अपनी हिट फिल्म के सेट पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाया था। इसके साथ ही उनपर मानहानी का दावा भी किया था। जिसमें उन्होंने करीब 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हर्जाने की मांग की थी। हालांकि जस्टिन ने इन आरोपों से इनकार किया। इसके विरुद्ध उन्होंने एक्ट्रेस पर जवाबी मुकदमा दायर किया था।

कानूनी विवाद में एंजेलीना जोली को मिली राहत, अदालत ने खारिज की ब्रैड पिट की याचिका

एक्स कपल ब्रैड पिट और एंजेलीना जोली के बीच शराब बनाने वाली कंपनी शैटो मिरावल को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। अब इस मामले में अदालत ने एंजेलीना जोली को राहत दी है और उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। लॉस एंजिल्स सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश ने ब्रैड पिट की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी वाइनरी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से जुड़े निजी ईमेल तक पहुंच की मांग की थी। पेज सिक्स द्वारा प्राप्त अदालती दस्तावेजों के अनुसार, अदालत ने फैसला सुनाया कि ब्रैड पिट एंजेलीना जोली के इस दावे को खारिज करने में अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाए हैं कि ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है। याचिका को खारिज कर दिया गया है। एंजेलीना जोली के कानूनी सलाहकार पॉल मर्फी ने इस फैसले को मामले का निर्णायक पल बताया। उन्होंने कहा, 'यह एंजेलीना जोली के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। यह फैसला दिखाता है कि ब्रैड पिट ने स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेजों तक पहुंच की मांग करके पूरी तरह से अपनी सीमाओं को पार किया था। उन्होंने शुरू में 126 प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी, लेकिन बाद में 22 पर आ गए। अब उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। यह एंजेलीना से जुड़ी हर चीज पर नियंत्रण रखने की ब्रैड पिट की आदत है, जिसमें उनके अपने वकीलों के साथ उनके बात करने पर नियंत्रण भी शामिल है। हमें बेहद खुशी है कि अपील न्यायालय और निचली अदालत दोनों ने अंततः इस पर रोक लगा दी। एक सूत्र ने आउटलेट को बताया कि एंजेलीना जोली ने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को गोपनीय बताकर रोक रखा है। ये ईमेल इस मामले में सबूतों का सिर्फ एक हिस्सा हैं। ब्रैड पिट एंजेलीना जोली द्वारा 2021 में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से जुड़े डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच की मांग कर रहे हैं। इसमें उनकी बिजनेस टीम के साथ हुए लेन–देन भी शामिल हैं। अक्तूबर 2025 में ब्रैड पिट के वकीलों ने कोर्ट में कुछ दस्तावेज जमा किए थे। इनमें एंजेलीना जोली की टीम और इस डील से जुड़ी कुछ दूसरी पार्टियों के डॉक्यूमेंट्स और सबूत थे। साथ ही दोनों के बीच की गोपनीय बातचीत थी, जिसे ब्रैड पिट और उनकी लीगल टीम कोर्ट में पेश कर चुकी थी। ये सबूत ये बताने के लिए थे कि आखिर एंजेलीना ने शराब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी आखिर बेची क्यों थी और इसके पीछे की वजह क्या थी। साथ ही इसमें कथित नुकसान का भी जिक्र था। पिट ने विशेष रूप से एंजेलीना जोली के बिजनेस मैनेजर टेरी बर्ड, उनकी ब्रिटिश प्रचारक क्लो डाल्टन और अर्मिका हेलिक, साथ ही वित्तीय सलाहकारों से संबंधित ईमेल तक पहुंच की मांग की थी। हालांकि, एक्ट्रेस का कहना था कि ये डॉक्यूमेंट्स उनकी कानूनी रणनीति का हिस्सा थे और इसलिए गोपनीय थे यह कानूनी विवाद ब्रैड पिट द्वारा 2022 में दायर एक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एंजेलीना जोली ने उनकी सहमति के बिना मिरावल में अपना हिस्सा स्टोली ग्रुप के वाइन डिवीजन टेनुटे डेल मोंडो को बेच दिया। जबकि उनके अनुसार पहले से एक समझौता हुआ था। एंजेलीना जोली ने ऐसे किसी समझौते से इनकार किया और पलटवार करते हुए पिट पर उनके खिलाफ बदले की भावना से केस दर्ज कराने का आरोप लगाया।

'गुल्लक' फेम निर्देशक के साथ फिल्म करेंगे ईशान खट्टर, निभाएंगे अलग तरह की भूमिका?

अभिनेता ईशान खट्टर ने अपने छोटे से करियर में अलग–अलग तरह के किरदार निभाए हैं। पिछले साल आई उनकी फिल्म 'होमबाउंड' को ग्लोबल स्तर पर काफी सराहा गया। फिल्म ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री भी थी। अब ईशान खट्टर एक बार फिर एक नए तरह के किरदार में नजर आने वाले हैं। दर्शकों ने ईशान को इस तरह के किरदार में पहले कभी नहीं देखा है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ईशान खट्टर अब एक कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक बिना नाम वाली इस फिल्म का निर्देशन पलाश वासवानी करेंगे, जो श्गुल्लकश जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में ईशान पहले ही मुख्य भूमिका में हैं। निर्माता अब फीमेल एक्ट्रेस और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। खबरों के अनुसार, फिल्म की शूटिंग अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। वर्कफ्रंट की बात करें तो ईशान खट्टर को आखिरी बार पिछले साल आई फिल्म 'होमबाउंड' में देखा गया था। नीरज घायवान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर प्रमुख भूमिका में नजर आए हैं। यह फिल्म उत्तर भारतीय शहर में दो बचपन के दोस्तों चंदन, एक दलित और शोएब एक मुस्लिम की कहानी है। दोनों पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। लेकिन परीक्षा परिणामों में देरी से सब कुछ बदल जाता है। ईशान अब श्द रॉयल्स सीजन 2श में नजर आएंगे। निर्माताओं ने इस साल की शुरुआत में सीरीज के दूसरे सीजन की घोषणा की थी।

'दर्शक खुद कर रहे प्रमोशन', रितेश देशमुख ने 'राजा शिवाजी' को मिल रही प्रतिक्रियाओं पर जताई खुशी

अभिनेता और निर्माता–निर्देशक रितेश देशमुख इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चाओं में हैं। रितेश ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है और उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका भी निभाई है। फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया हासिल हुई है। वहीं क्रिटिक्स से भी फिल्म को मिली–जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। अब रितेश ने फिल्म के प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए आधुनिक दर्शकों के लिए इसके महत्व पर जोर दिया है। एएनआई से बात करते हुए रितेश देशमुख ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से परे, इमोशनली दर्शकों से जुड़ सकी। अभिनेता ने कहा कि जब मैं लोगों को अपने परिवार के साथ, समूह बनाकर, अपने दादा–दादी को लेकर फिल्म देखने जाते देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी फिल्म नहीं देखी। नए माता–पिता, एक साल का बच्चा और दो साल का बच्चा चाहते हैं कि उनके जीवन की पहली फिल्म राजा शिवाजी हो, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म। वे फिल्म देखने के लिए अंदर जाकर अपने वीडियो बना रहे हैं। अंदर जाने के बाद हर किसी को कुछ महसूस होता है। बाहर आने के बाद वे वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और लोगों से इस फिल्म को देखने का आग्रह करते हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर दर्शकों और प्रशंसकों द्वारा सिनेमाघरों में जश्न मनाते हुए वीडियो और फिल्म पर अपनी राय साझा करने की बाढ़ आ गई है। रितेश ने इसे ऑर्गेनिक प्रमोशन बताया और कहा कि यही किसी फिल्म की सच्ची सफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यही वो पल है जब दर्शक किसी फिल्म को स्वीकार करते हैं। फिल्म निर्माताओं के लिए यह एहसास बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब दर्शक किसी फिल्म को स्वीकार करते हैं, तो वे खुद ही उसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं। हम जैसे फिल्मकारों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 'राजा शिवाजी' छत्रपति शिवाजी और बीजापुर साम्राज्य के सेनापति अफजल खान के बीच की प्रतिद्वंद्विता को दिखाती है। फिल्म में शिवाजी के बीजापुर और मुगलों के खिलाफ सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। अपनी फिल्म के महत्व के बारे में बताते हुए रितेश ने कहा कि मुझे लगता है कि बच्चों को यह फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि इतिहास के कुछ ही पन्ने हमारे सामने आते हैं। मेरा मानना है कि जब कोई कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि इतिहास की किताबों में बहुत सी बातें नहीं दिखाई जातीं। यह सब जानने के लिए इस फिल्म को देखना जरूरी है। रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में भी अच्छी कमाई कर रही है। पांच दिनों में भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 44.40 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है।

लहसुन छीलने में अब नहीं होगी कोई दिक्कत, खाना भी बन जाएगा झटपट

ज्यादातर लोग खाना बनाते समय लहसुन का इस्तेमाल करते है। जिसकी वजह से खाने में खुशबू बहुत अच्छी आती है। बता दें कि विंटर में सूप या स्ट्यू बनाने हो, चिकन करी बनाना हो या कोई स्ट्वादिष्ट सब्जी या कबाब हर खाने में लहसुन होना सबसे जरूरी समझा जाता है। ऐसे में ताजा लहसुन छीलना कई लोगों के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। तो चलिए आज हम आपको लहसुन को असानी से छीलने के तरीकों के बारे में बताएंगे।

पहला तरीका

लहसुन को गर्म करके भी उसे आसानी से छीला जा सकता है। इसके लिए आप कड़ाही में लहसुन को गर्म करने के अलावा माइक्रोवेव की मदद भी ले सकते हैं। बस आप 30 सेकंड के लिए लहसुन को माइक्रोवेव में रखें और फिर उसके बाद लहसुन को छीलें। लहसुन काफी जल्दी छील जाएगा।

दूसरा तरीका

एक कटोरे में हल्का गुनगुना पानी लें। इस पानी में लहसुन भिगो कर रख दें। फिर लहसुन को हाथ से रगड़ें, जिससे आसानी से छिलका निकल जाएगा।

तीसरा तरीका

बेलन जिस तरह आटे की लोई पर चलाया जाता है, उसी तरह उसे लहसुन पर चलाएं। ऐसे में छिलके खुद–ब–खुद खुल जाएंगे जिन्हें बाद में आप हटा सकते हैं।

चौथा तरीका

अगर लहसुन अधिक मात्रा में है तो उसे हल्की गर्म कड़ाही में 2 से 3 मिनट के लिए भुन लें। फिर ठंडा होने के बाद लहसुन छीलें। इससे छिलका आसानी से उतर जाएगा।

पांचवा तरीका

लहसुन को कम से कम 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। उसके बाद लहसुन छीलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। छीलते वक्त लहसुन का पानी फेंके नहीं। पानी की मदद से साथ–साथ हाथों पर लगने वाले छिलके उतारती जाएं।

बालों की खूबसूरती को बढ़ाने में काम आएंगे ये टिप्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा बदलाव

हमारी खूबसूरती को बनाए रखने में बालों की बहुत अहम भूमिका होती है। स्वस्थ और घने बाल सभी को पसंद होते है। बाल बेजान और चमकहीन हों तो हमारी सुंदरता पर दाग लग जाता है। यदि आप अपने बालों की देखभाल सही तरीके से नहीं करते हैं तो स्किन की देखभाल का कोई खास फायदा नहीं है। इन्ह्हीं बातों को ध्ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ घरेलू टिप्स बताएंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।

अंडे का करें इस्तेमाल

बालों को हेल्दी और शाइनी बनाने के लिए अंडे से बेहतर कुछ नहीं है। अंडे में प्रोटीन, फैटी एसिडस और लैक्टिन होता है, जो बालों की मरम्मत करता है। यदि आप इसमें ऑलिव ऑयल मिलाकर लगाती हैं, तो ज्यादा और जल्दी असर देखने को मिलेगा।

नारियल तेल का इस्तेमाल

बालों के लिए आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बाल मुलायम और चमकदार तो बनते ही हैं, साथ ही

बालों में नई चमक भी आती है। नारियल तेल में विटामिन ई होता है, जो बालों को नमी देता है और बालों को रूखा होने से बचाता है।

एलोवेरा का इस्तेमाल

बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अपने बालों में एलोवेरा जेल लगाएं। इससे बाल काफी जल्दी लंबे हो सकते हैं। इसके लिए फ्रेश एलोवेरा जेल को काटकर इसे अपने बालों में लगाकर करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब नॉर्मल शैंपू से अपने बालों को धो लें. इसे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी।

आपकी प्लेट ही आपकी सेहत तय करती है । पर जाने–आनजाने में आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। अब केले को ही देख लीजिए भले ही सेहत के लिए अच्छा है इसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं पर इसे लेकर की गई गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर ने केले से जुड़ी दो गलतियों के बारे में बताया है जो शरीर को नुकसान दे सकती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

केले को कच्चा या बहुत ज्यादा पका हुआ खाना

डॉक्टर की ओर से सलाह दी गई है कि केला खाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि यह कितना पका हुआ है। एक आम गलती यह है कि लोग केले खाते समय उसके पकने के स्तर पर ध्यान नहीं देते। बहुत ज्यादा पके हुए या कच्चे केले पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कच्चे फलों में रेसिस्टेंट स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। रेसिस्टेंट स्टार्च एक प्रीबायोटिक होता है, लेकिन अक्सर संवेदनशील लोगों को इससे पेट फूलने और गैस की समस्या हो जाती है, क्योंकि उनके पेट को इसे पचाने में दिक्कत होती है। वहीं काले हो चुके केलों को भी खाने से बचना चाहिए। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने इसकी वजह बताते हुए कहा–बहुत ज्यादा पके हुए केलों में सिंपल शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक से नीचे गिर जाता है। केले तब खाने चाहिए जब उनका छिलका चमकीला पीला हो और उस पर बस कुछ ही भूरे रंग के धब्बे हों।

केला खाते समय कभी ना करना ये दो बड़ी गलतियां, नहीं तो हमेशा परेशान रहेगा आपका पेट

खाली पेट खाना

आपको लग सकता है कि सुबह सबसे पहले केला खाने से आपके दिन की शुरुआत हेल्दी होती है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं हो सकता। असल में केले में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, पोटैशियम और मैग्नीशियम, अगर आप केले को खाली पेट खाते हैं तो उन्हें बेअसर कर सकते हैं। डॉक्टर ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति केले में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और पोटैशियम को बिना किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के खाली पेट खाता है, तो कभी–कभी ब्लडस्ट्रीम में टेम्पररी मिनरल इम्बैलेंस हो जाता है। इससे आपको सुस्ती महसूस हो सकती है, और आपका पेट भी खराब हो सकता है।

केले को खाने का सही तरीका

डॉक्टर ने सलाह दी कि केले को अकेले खाने के बजाय अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि पोषक तत्वों के मिश्रण के साथ खाने पर पाचन क्रिया बेहतर होती है। एक चम्मच नट बटर मिलाने या केले को ग्रीक योगर्ट में मिलाकर खाने से चीनी का अवशोषण धीमा हो जाता है। उन्होंने ऊर्जा स्तर को स्थिर रखने और पाचन तंत्र द्वारा केले के सुचारू पाचन को सुनिश्चित करने में इस संयोजन के महत्व पर जोर दिया। ग्रीक योगर्ट के साथ केले खाने से किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावना समाप्त हो जाती है।

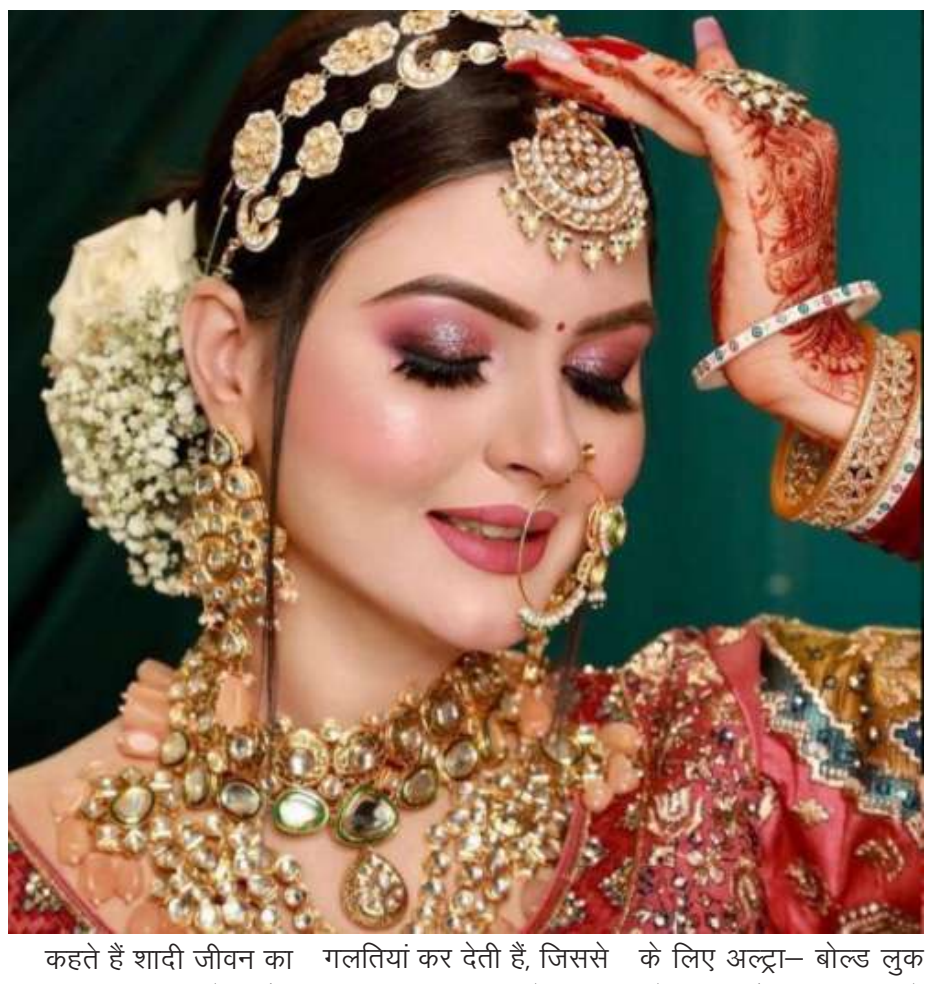

ब्राइडल मेकअप करते हुए ये गलतियां कर सकती हैं पूरा लुक खराब, सुंदर की जगह दिखेंगी डरावनी!

कहते हैं शादी जीवन का दूसरा नया पड़ाव होता है। ऐसे में लड़कियां अपने डी–डे वाले दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत और अलग दिखना चाहती हैं। ऐसे में वह बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट की तलाश करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, जब वे मेकअप आर्टिस्ट कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिससे की पूरा लुक खराब हो जाता है। ऐसे में हम बता रहे हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनका ध्यान दुल्हन को मेकअप के दौरान खुद से रखना चाहिए....

बोल्ड लिप्स और आंखे

इन दिनों अक्सर लड़कियां अपने ब्राइडल लुक के लिए अल्ट्रा– बोल्ड लुक को चुनती हैं। इस लुक को फॉलो करने के लिए सबसे ध्यान रखें कि आपकी आंखों और लिप्स दोनों में से कोई एक ही बोल्ड हो। अगर आपने होठों के लिए बोल्ड शेड चुना है तो आपका आई मेकअप पेस्टल शेड्स में होना चाहिए। वहीं अगर आपने अपनी आंखों को बोल्ड रंगों में किया है, तो न्यूड रंग से अपने लिप्स को चुनें।

बहुत ज्यादा ब्लश अप्लाई करना

ब्लशर आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा लगाने से परेशानी हो सकती है। ब्लश चेहरे को काफी आकर्षक और आर्टिफिशियल बनाता है। इसलिए ध्यान रखें कि आपका मेकअप आर्टिस्ट ब्लश को ठीक से ब्लेंड करें, ऐसा करने से आपको नेचुरल लुक मिलेगा । ब्लशर लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सॉफ्ट स्ट्रोक का इस्तेमाल करें। ये गालों को फ्रेश लुक देगा।

बेस अप्लाई न करना

ज्यादातर लोग इस बात को भूल जाते हैं। चेहरे पर तो हर को अपने बेस को अप्लाई कर लेता है, लेकिन दूसरे हिस्सों, जैसे पीठ, बाहों, कंधों जैसी जगहों पर मेकअप बेस लगाने में अक्सर लोग चूक कर जाते हैं। ऐसे में ये हिस्से आपके चेहरे से अलग दिखने लगते हैं। ध्यान रखें कि आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से इन सभी जगहों पर मेकअप लगाने को कहें।

महिलाओं की इन आदतों से नाराज हो जाती है मां लक्ष्मी, घर में आती है दरिद्रता और आर्थिक संकट

हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र की विशेष मान्यता हैं। इसमें माता लक्ष्मी की पूजन विधि और प्रसन्न करने के तरीकों भी बताया गया है। वास्तु शास्त्र में घर की महिलाओं के किन कार्यों से मां लक्षमी नाराज हो जाती है, इसके बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार कौन से कार्य हैं, जिनको महिलाओं को नहीं करना चाहिए नहीं तो मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसेगी...

सूर्योदय के बाद ना करे सफाई

वास्तु शास्त्र के नियमों के हिसाब से महिलाओं को घर की सफाई सूर्योदय से पहले कर लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद सफाआई करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं।

बिना सन्ना ना करें रसोई में प्रवेश

बिना नहाएं महिलाओं को रसोई में खाना बनाने के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है।

देर से ना करें स्नान

वास्तु शास्त्र के नियमों के हिसाब से सूर्योदय से पहले साफ–सफाई करने के बाद सुबह जल्दी नहा लेना चाहिए। देरी से नहाने पर घर में दरिद्रता आती है।

प्रसाद चढ़ाने के बाद करें भोजन

नहाने के बाद महिलाओं को मां लक्ष्मी को रोजाना प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने से पहले खाना खाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं।

शाम को ना करें बालों में कंघी

वास्तु शास्त्रों के नियमों के मुताबिक महिलाओं को शाम को बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती और घर में दरिद्रता आती है।

क्रोध ना करें

महिलाओं को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के नियमों के हिसाब से ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है।

संक्षिप्त

ईरान–अमेरिका तनाव घटने की उम्मीद से शेयर बाजार में तेजी

नई दिल्ली,एजेंसी। बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों के लिए शानदार शुरुआत हुई। वैश्विक मोर्चे पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और भू–राजनीतिक तनाव के जल्द सुलझने की उम्मीदों ने बाजार की धारणा को काफी मजबूत किया है। इसके चलते शुरुआती कारोबार में ही प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आधे–आधे प्रतिशत की जोरदार बढ़त दर्ज की गई और बाजार में हरियाली छा गई। बाजार खुलते ही निवेशकों की भारी खरीदारी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 657.22 अंक उछलकर 77,675.01 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 218 अंकों की मजबूत रैली के साथ 24,250.85 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। शुरुआती रुझानों के अनुसार, सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक चढ़ा, जबकि निफ्टी ने 24,150 का अहम स्तर पार कर लिया। रुपया सर्वकालिक निचले स्तर से उबरते हुए शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे बढ़कर 94.99 पर पहुंच गया। शेयर बाजार में इस सकारात्मक रुख के पीछे मुख्य रूप से कुछ बड़े वैश्विक और आर्थिक कारण रहे हैं। व्यापक बाजार की इस तेजी के बीच, कॉर्पोरेट जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में बुधवार को बीएसई पर 3.2 प्रतिशत तक की उछाल दर्ज की गई और शेयर 11.15 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी का मुख्य कारण कंपनी के शीर्ष नेतृत्व में हुआ बड़ा बदलाव है। अरबपति उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को दूरसंचार फर्म में फिर से गैर–कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि लगभग पांच साल पहले, जब कंपनी भारी वित्तीय संकट से घिरी थी, तब बिड़ला ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। पांच साल बाद उनकी इस वापसी को बाजार ने काफी सकारात्मक रूप से लिया है।

सरकार ने लागू किया एलपीजी का नया नियम! ऐसा न करने पर सीधे कटेगा गैस कनेक्शन

नई दिल्ली,एजेंसी। अगर आपके घर में भी रसोई गैस सिलेंडर और पाइप वाली गैस दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार अब एक घर, एक कनेक्शन (व्दम भ्वनेमीवसक, व्दम ब्वददमबजपवद) के नियम को बेहद सख्ती से लागू कर रही है। नए नियमों के मुताबिक, किसी भी एक परिवार के लिए सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी कनेक्शन दोनों को एक साथ रखना अब पूरी तरह से गैर–कानूनी घोषित कर दिया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके चलते सरकार ने गैस के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है।सरकार का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि गैस सिलेंडर केवल उन जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे, जहां अभी तक पीएनजी की पाइपलाइन नहीं बिछी है। दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में गैस कंपनियां अब ऐसे घरों की पहचान कर रही हैं, जो दोनों कनेक्शन का एक साथ फायदा उठा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के तहत ऑयल कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को साफ निर्देश दिए गए हैं कि पीएनजी वाले घरों को नया एलपीजी सिलेंडर जारी या रीफिल न किया जाए। एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करें– अगर आपके घर में पीएनजी (पाइपलाइन गैस) चालू हो चुकी है, तो आपको तुरंत अपना पुराना एलपीजी गैस कनेक्शन सरेंडर (वापस) करना होगा।

स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं लोग– अब तक देश भर में 43,000 से अधिक उपभोक्ता स्वेच्छा से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन सरकार के पास मौजूद डेटा के अनुसार ऐसे घरों की संख्या काफी अधिक है।

कार्रवाई की चेतावनी– अगर कोई परिवार इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और बिना किसी पूर्व सूचना के उसका कनेक्शन भी रद्द किया जा सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88प्रतिशत कच्चा तेल, 50प्रतिशत प्राकृतिक गैस और लगभग 60प्रतिशत एलपीजी विदेशों (मुख्य रूप से सऊदी अरब और यूएई) से आयात करता है। ईरान–इजराइल तनाव और वैश्विक संकट के कारण गैस सप्लाई काफी सीमित हो गई है। इसका असर न केवल घरों पर, बल्कि होटलों, रेस्तरां और कॉमर्शियल यूनिट्स पर भी पड़ रहा है, जहां एलपीजी की कम आपूर्ति के चलते वैकल्पिक ईंधन अपनाने को कहा जा रहा है। इसलिए, अगर आपके पास भी डबल कनेक्शन है, तो परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द एक कनेक्शन सरेंडर कर दें। सबसे अधिक घरों में 14.2 किलो वाला सिलेंडर इस्तेमाल होता है। आज दिल्ली में यह एलपीजी सिलेंडर 913 में मिल रहा है। वहीं, छोटे परिवार या अस्थायी उपयोग के लिए 5 किलोग्राम का सिलेंडर 339 में उपलब्ध है।

पाकिस्तान सुपर लीग की टीम ऑफ द टूर्नामेंट पर भड़के डेविड वॉर्नर

कराची,एजेंसी। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का खिताब पेशावर जाल्मी ने जीत लिया, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होते ही सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वॉर्नर ने पीएसएल की टीम ऑफ द टूर्नामेंट चयन पर सवाल उठाकर हलचल मचा दी। पेशावर जाल्मी ने फाइनल में डेब्यू करने वाली हैदराबाद किंग्समेन को पांच विकेट से हराकर अपना दूसरा पीएसएल खिताब जीता। बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम पूरे सीजन शानदार लय में दिखी और लीग चरण में सिर्फ एक मैच हारी। खिताब जीत के बाद पीएसएल ने अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की, लेकिन इसमें कराची किंग्स का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं था। इसी बात पर डेविड वॉर्नर ने नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा, श्कराची के खिलाड़ी कहां हैं? वॉर्नर का यह छोटा सा बयान तेजी से वायरल हो गया। फैंस भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों ने वॉर्नर का समर्थन किया, तो कुछ ने कहा कि कराची किंग्स छठे स्थान पर रही थी, इसलिए खिलाड़ियों का चयन नहीं होना स्वाभाविक है। कराची किंग्स इस सीजन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। टीम अंक तालिका में छठे स्थान पर रही और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। ऐसे में टीम के किसी खिलाड़ी को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ एकादश में जगह नहीं मिली। हालांकि वॉर्नर का मानना था कि व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर कुछ खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता था। यही वजह है कि उन्होंने खुलकर सवाल उठाया। दूसरी ओर पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम ने जीत के बाद पूरी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि टीम और फैंस की भी है। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि पेशावर जाल्मी और सभी फैंस के लिए भी है। पूरे टूर्नामेंट में हमने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया और अपने क्रिकेट का आनंद लिया। हर खिलाड़ी ने योजनाओं को सही तरीके से लागू किया। हमारा लक्ष्य मैच दर मैच आगे बढ़ना था और भगवान की कृपा से आज हम जीत गए। बाबर ने टीम मैनेजमेंट की भूमिका को भी अहम बताया। उन्होंने कहा, श्योजना के स्तर पर मैनेजमेंट ने हमेशा हमारा समर्थन किया। हर मैच के बाद हम अपनी अच्छी और कमजोर बातों पर खुलकर चर्चा करते थे। पीएसएल 2026 का खिताब पेशावर जाल्मी ने जीत लिया, लेकिन डेविड वॉर्नर के एक सवाल ने टूर्नामेंट के अंत में नई बहस जरूर छेड़ दी।

निराश सात्विक का टूटा दिल, चिराग- प्रणय ने दिया झकझोर देने वाला बयान

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सत्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थॉमस कप 2026 में कांस्य पदक जीतने के बाद बड़ा बयान देकर खेल जगत में बहस छेड़ दी है। दोनों खिलाड़ियों ने साफ कहा कि भारत अभी भी खेल राष्ट्र नहीं बना है और यहां बैडमिंटन जैसी उपलब्धियों को वह सम्मान नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए। सबसे चौंकाने वाला बयान सत्विक का रहा, जिन्होंने कहा कि वह अपने बच्चे को बैडमिंटन नहीं खिलाना चाहेंगे। डेनमार्क में थॉमस कप में पदक जीतने के बाद जब भारतीय टीम स्वदेश लौटी, तो खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि देश इस सफलता पर गर्व करेगा, लेकिन एयरपोर्ट पर जो हुआ, उसने खिलाड़ियों को निराश कर दिया। सत्विक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लिखा था, श्घर लौट आए हैं। हमेशा की तरह किसी को नहीं पता कि पिछले दो हफ्तों में क्या हुआ, और लगता है किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। बाद में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया, हम जर्मनी से सात घंटे की फ्लाइट लेकर हैदराबाद पहुंचे। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि हम कौन हैं या कौन सा मेडल जीतकर आए हैं। हम थॉमस कप की जर्सी पहने थे, लेकिन सब लोग आईपीएल, राजनीति या दूसरी चीजों में व्यस्त थे। सत्विक ने याद दिलाया कि 2022 में भारत ने पहली बार थॉमस कप गोल्ड जीता था, लेकिन तब भी जश्न वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। उन्होंने कहा, जब हम 2022 में जीते थे, तब भी इसे और बड़े स्तर पर मनाया जाना चाहिए था। लोग नहीं समझते कि ऐसे मौके बार–बार नहीं आते। थॉमस कप जीतना बहुत मुश्किल है, मेडल जीतना भी आसान नहीं।श उन्होंने आगे कहा, एयरपोर्ट पर प्रणय, श्रीकांत और ध्रुव जैसे खिलाड़ी खुद कैब बुक कर रहे थे। मेरे दोस्त मुझे लेने आए थे, लेकिन वह दृश्य देखकर मैं बहुत दुखी था। सत्विक ने सबसे बड़ा बयान तब दिया जब उन्होंने भविष्य को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, श्मैंने प्रणय से कहा कि मैं अपने बच्चे को बैडमिंटन नहीं खेलने दूंगा। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो संभाल लेंगे, वरना जब देश का बड़ा हिस्सा आपकी मेहनत से अनजान हो, तब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें बड़े सम्मान की अपेक्षा नहीं है। सात्विक ने कहा, श्हैदराबाद अकादमी में हमें सम्मान मिला, छोटा सा बुके मिला, केक कटा, वही काफी था। हमें कुछ भव्य नहीं चाहिए। सत्विक के जोड़ीदार चिराग शेट्टी ने भी निराशा जताई। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि भारत में कुछ खेलों को छोड़ बाकी उपलब्धियों की अहमियत अब भी नहीं समझी जाती। उन्होंने कहा, हमें एयरपोर्ट पर भीड़ की उम्मीद नहीं थी। पिछली बार जब हम जीते थे, हमारा स्वागत हुआ था, प्रधानमंत्री से मिले थे, सम्मान भी मिला था। लेकिन उस जीत का जश्न वैसा नहीं मनाया गया जैसा होना चाहिए था। जो लोग बैडमिंटन देखते हैं, वे समझते हैं, लेकिन आम जनता 2022 की जीत की अहमियत नहीं समझती। यह सोचकर दुख होता है कि हम अभी तक स्पोर्टिंग नेशन नहीं बने हैं। चिराग ने कहा, हां, हम बहुत सारे मेडल जीतते हैं, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों का जश्न उस तरह नहीं मनाते जैसे मनाना चाहिए। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकार और खेल संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन पूरे खेल माहौल को खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सम्मान करना शुरू करना होगा। यह कोई पहली बार नहीं है। चिराग पहले भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। एचएस प्रणय ने भी खिलाड़ियों की भावना समझाई।

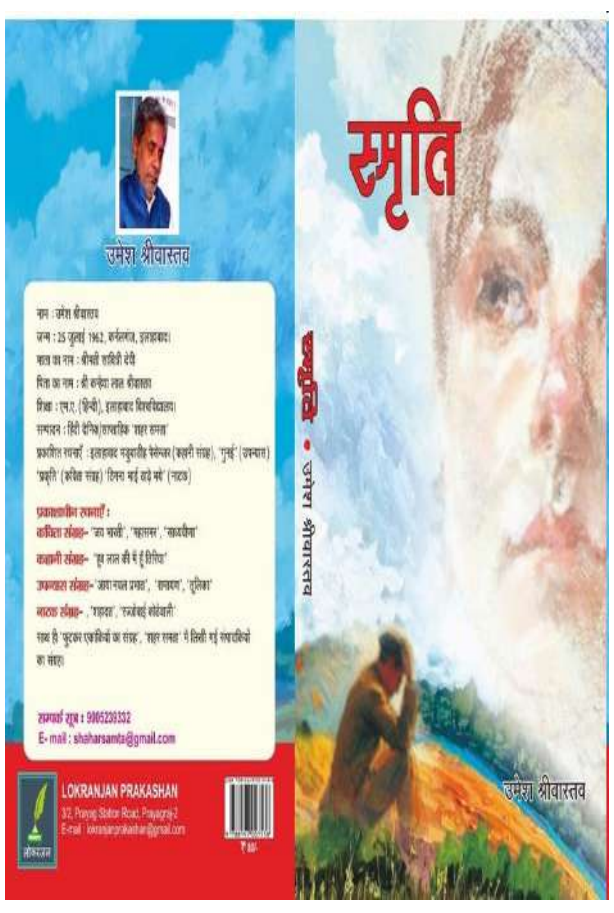

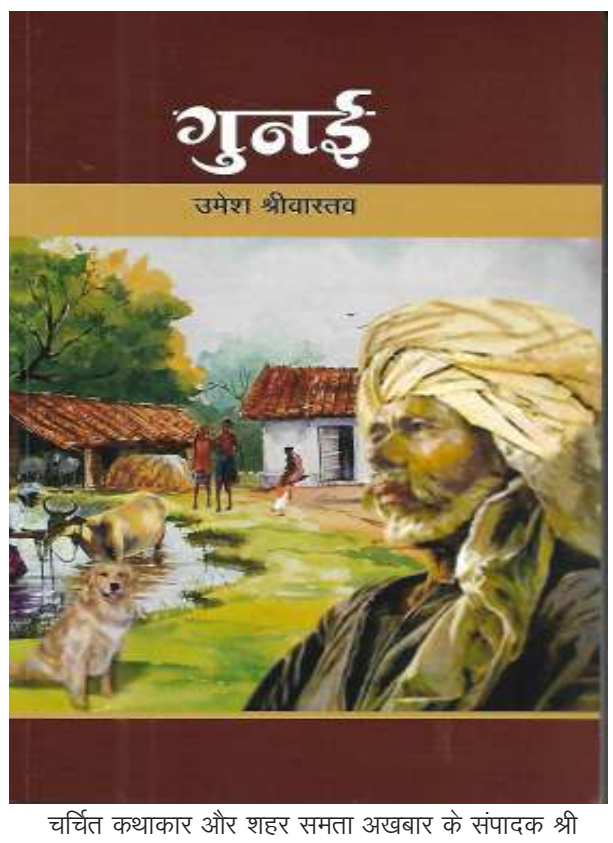

चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित

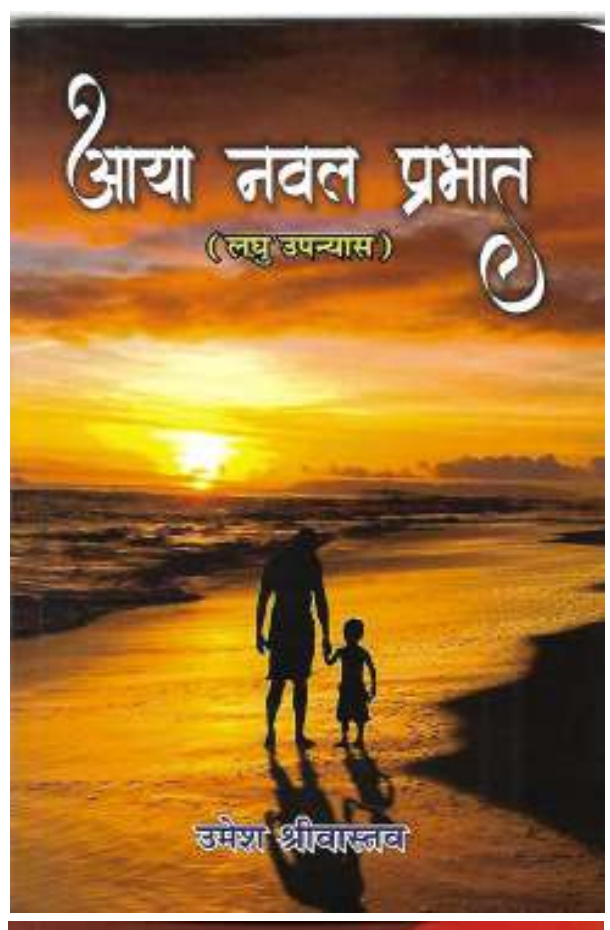

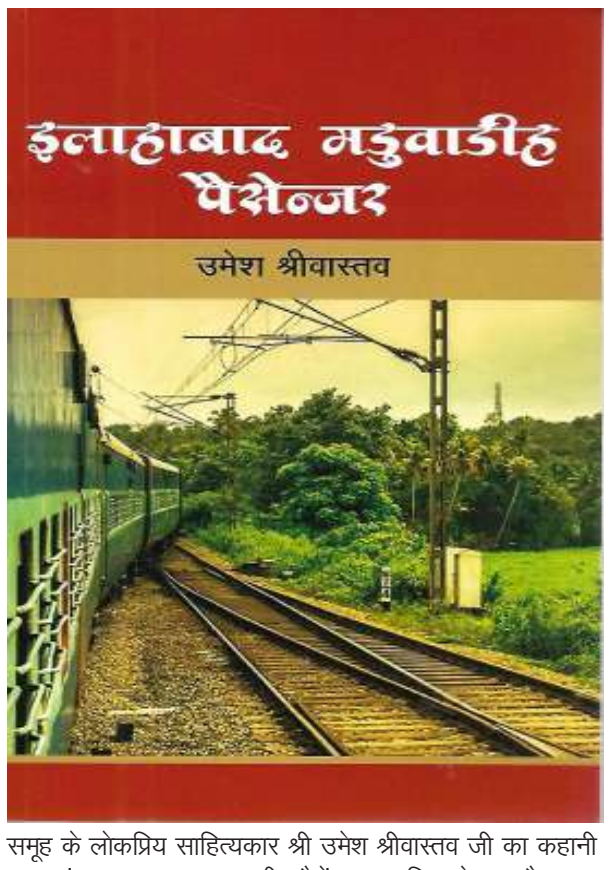

समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।

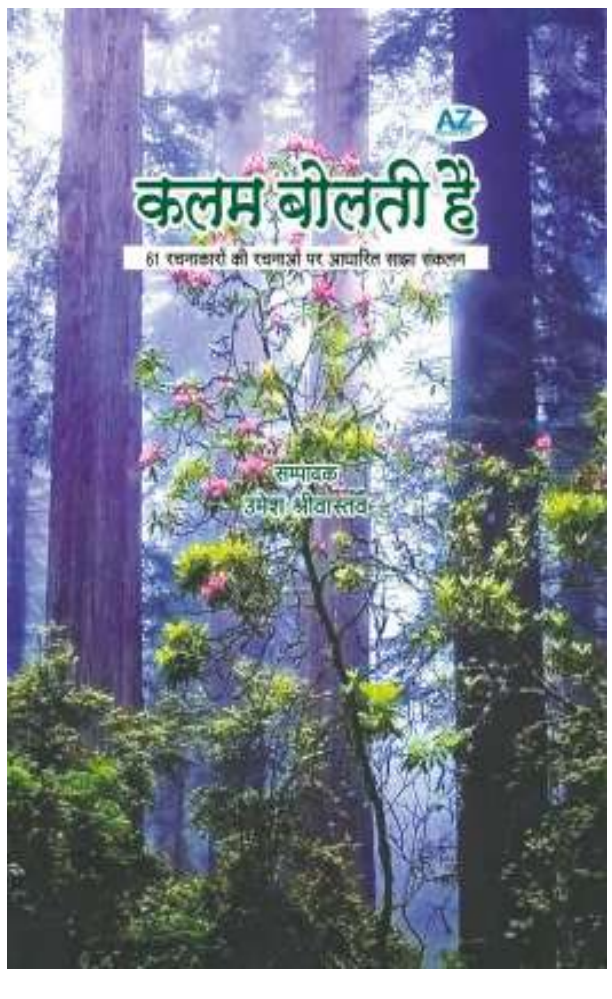

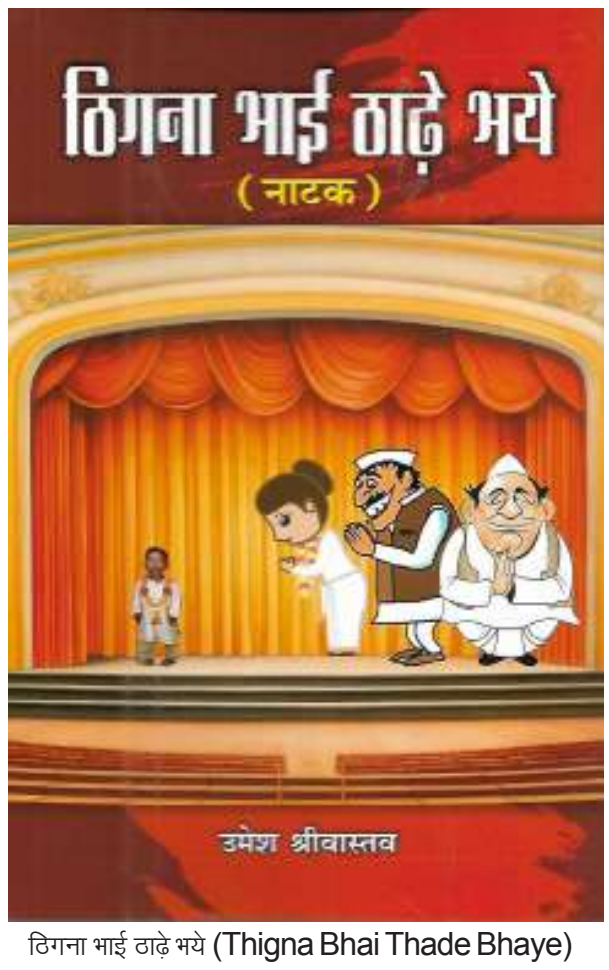

ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

संक्षिप्त

जमैका के बाद सूरीनाम पहुंचे जयशंकर, पारामारीबो में हवाई अड्डे पर हुआ गर्मजोशी से स्वागत

पारामरिबो (सूरीनाम), एजेंसी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को सूरीनाम पहुंचे, जहां उनकी वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। तीन कैरिबियाई देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उन्होंने अपने समकक्ष मेल्विन

बुवा से मुलाकात की, जिन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जयशंकर ने कहा कि वह पहली बार पारामारीबो (सूरीनाम की राजधानी) पहुंचे हैं और बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और सूरीनाम के बीच खास संबंध हैं, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में गिरमिटिया समुदाय के लोग रहते हैं। ये वे भारतीय मजदूर थे जो 19वीं सदी में अनुबंध के तहत विदेश में काम करने गए थे और बाद में वहीं बस गए। इस यात्रा के बाद जयशंकर त्रिनिदाद और टोबैगो भी जाएंगे। इससे पहले वह जमैका का दौरा कर चुके हैं, जहां कई अहम समझौते हुए और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। भारत ने जमैका को स्वास्थ्य और आपदा राहत के तहत डायलिसिस यूनिट, मछली पकड़ने वाली नावें और जीपीएस उपकरण देने का निर्णय लिया है। यह सहायता पिछले साल आए तूफान के बाद पुनर्निर्माण में मदद के लिए दी जा रही है। इन क्षेत्रों में सहयोग करने पर जताई सहमति जयशंकर ने जमैका में कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए और दोनों देशों ने डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए जमैका के समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ रुख पर एकुजटता की सराहना की। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और वहां के विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

दशकों पुराना तीस्ता जल विवाद सुलझेगा?: बंगाल में BJP की जीत से गदगद हुआ बांग्लादेश, ममता पर लगाए कई गंभीर आरोप

ढाका, एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ऐतिहासिक जीत का असर अब सीमाओं के पार भी दिखने लगा है। इस बड़ी चुनावी जीत ने क्षेत्रीय कूटनीति और राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव का

संकेत दिया है। बांग्लादेश की सत्ताधारी श्बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टीश (बीएनपी) ने पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज करने पर भाजपा को औपचारिक रूप से अपनी बधाई दी है। यह सिर्फ एक चुनावी जीत की बधाई नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच दशकों पुराने जल विवादों के जल्द सुलझने की एक नई और मजबूत उम्मीद भी जगी है। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। हेलाल ने कहा कि वह विजेता पार्टी भाजपा और शुभेंदु अधिकारी को बधाई देते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की यह जीत सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सरकार के बीच संबंध पहले की तरह ही अच्छे और मजबूत बने रहें। बीएनपी की इस प्रतिक्रिया ने ढाका और कोलकाता के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा पार विवादों को लेकर कूटनीतिक उम्मीद का एक दुर्लभ और सकारात्मक क्षण पेश किया है। उनका मानना है कि यह सत्ता परिवर्तन दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के साथ-साथ काफी बेहतर बनाएगा। ममता के सत्ता से हटने पर सुलझेगा तीस्ता जल विवाद? बीएनपी के इस पूरे बयान में सबसे अहम बात तीस्ता जल बंटवारा संधि को लेकर कही गई है, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से अधर में लटकी हुई है। बीएनपी के नेता हेलाल ने सीधे तौर पर निवर्तमान तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व और विशेषकर ममता बनर्जी को इस समझौते में सबसे बड़ी बाधा बताया है। बीएनपी का दावा है कि ममता बनर्जी का पिछला प्रशासन ही तीस्ता बैराज समझौते में रुकावट डाल रहा था। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि अब चूंकि पश्चिम बंगाल की सत्ता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के हाथ में आ गई है, इसलिए राज्य सरकार इस संधि को अंतिम रूप देने के लिए मोदी प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी। हेलाल ने स्पष्ट कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जगह भाजपा के सत्ता में आने से अब तीस्ता बैराज परियोजना को जरूर लागू किया जाएगा। नदियों के पानी को लेकर क्या है पुराना विवाद?

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र

शहर समता हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र

मोबाईल नम्बर 9190052 39332

919450482227

स्टार्मर की मुश्किलें बढ़ीं?: स्थानीय चुनावों में भारी नुकसान का डर, जानें पार्टी में क्यों उठे बगावत के सुर

लंदन , एजेंसी। ब्रिटेन में इस वक्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। गुरुवार को होने वाले स्थानीय चुनाव ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। इन चुनावों के नतीजे यह तय कर सकते हैं कि स्टार्मर अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह चुनाव साबित कर देंगे कि अब ब्रिटेन एक बंटी हुई राजनीति के दौर में प्रवेश कर चुका है। माना जा रहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री से काफी नाराज है और इसका सीधा असर चुनाव की वोटिंग में देखने को मिलेगा। ब्रिटेन की राजनीति अब कई अलग-अलग पार्टियों में बंटती हुई नजर आ रही है, जिससे सत्ताधारी पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। कीर स्टार्मर की श्लेबर पार्टीश को इंग्लैंड की स्थानीय परिषदों के साथ-साथ स्कॉटलैंड और वेल्स की विधानसभाओं में होने वाले इन चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कमजोर अर्थव्यवस्था और जनता की नाराजगी के कारण प्रधानमंत्री की लोकप्रियता काफी नीचे गिर गई है। विपक्षी पार्टियां गुरुवार को होने वाले इस चुनाव को स्टार्मर सरकार के दो साल के कामकाज पर एक कड़े जनमत संग्रह की तरह पेश कर रही हैं। धुर-दक्षिणपंथी पार्टी श्रिफॉर्म यूकेश ने तो इस चुनाव में अपना खास नारा ही श्रिफॉर्म को वोट दें, स्टार्मर को बाहर करें् रख लिया है। वैसे तो अगला राष्ट्रीय चुनाव साल 2029 तक नहीं होना है, लेकिन अगर गुरुवार को लेबर पार्टी बुरी तरह हारती है, तो स्टार्मर के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी में एक बड़ी बगावत शुरू हो सकती है। एक विशेषज्ञ के अनुसार, भारी जीत के दो साल के अंदर ही स्टार्मर अब लोगों की निराशा का बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही कीर स्टार्मर ने कई ऐसी गलतियां की हैं, जिससे उनकी साख को भारी धक्का लगा है। उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, खस्ताहाल बुनियादी सेवाएं सुधारने और महंगाई कम करने के अपने वादों में पूरी तरह नाकाम रही है। इसके साथ ही, ईरान के साथ अमेरिकी-इस्राइली युद्ध के कारण यह काम और भी मुश्किल हो गया है। इस युद्ध ने होर्मुज के रास्ते से आने वाले तेल की सप्लाई को रोक दिया है। इसके अलावा, एक दागी छवि वाले पीटर मैंडेलसन को वाशिंगटन का राजदूत बनाने के उनके अजीब फैसले से भी देश की जनता और पार्टी के नेता बहुत ज्यादा खफा चल रहे हैं। जानकारों का अनुमान है कि लेबर पार्टी इंग्लैंड की 2,500 में से आधी से ज्यादा सीटें बहुत बुरी तरह हार सकती है। यह लेबर पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। अगर चुनाव में इतनी करारी हार होती है, तो स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग, पूर्व उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर या मेयर एंडी बर्नहैम जैसे बड़े नेता स्टार्मर को पद से हटाने के लिए सीधी चुनौती दे सकते हैं। नियम के अनुसार किसी भी नेता को ऐसा करने के लिए संसद में कम से कम 80 सांसदों के समर्थन की सख्त जरूरत होगी। जानकारों का साफ कहना है कि अब यह सवाल नहीं है कि स्टार्मर जाएंगे या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि वह कब जाएंगे। दशकों से ब्रिटेन में केवल दो ही मुख्य पार्टियां सत्ता के आस-पास रही हैं, लेकिन अब यहां की राजनीति पूरी तरह बदल रही है। इस बार लेबर पार्टी का वोट श्ग्रीन पार्टीश और श्रिफॉर्म यूकेश जैसी पार्टियों में बंटने की पूरी उम्मीद है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ब्रिटेन अब श्पांच-पार्टी सिस्टमश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वेल्स में एक सदी से राज कर रही लेबर पार्टी अब तीसरे नंबर पर खिसक सकती है और वहां श्प्लेड सिमरूश पार्टी चुनाव जीत सकती है। वहीं, स्कॉटलैंड में श्स्कॉटिश नेशनल पार्टीश ने कड़ा ऐलान किया है कि अगर वह चुनाव जीती तो ब्रिटेन से आजादी के लिए एक नया जनमत संग्रह कराएगी। अब पुरानी राजनीति खत्म हो रही है और बदलाव तय माना जा रहा है।

पाकिस्तान के पेशावर में अमेरिका बंद करेगा वाणिज्य दूतावास, सुरक्षा के डर से ट्रंप का फैसला

चेन्नई , एजेंसी। अमेरिका ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर शहर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को पूरी तरह से बंद करने का बड़ा एलान कर दिया है। यह फैसला अचानक एक झटके में नहीं लिया गया है, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से यानी धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। अमेरिका के इस बड़े फैसले से पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने दुनिया को साफ कर दिया है कि उसके लिए अपने राजनयिकों और कर्मचारियों की जान की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और वह इस मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी करके इस बड़े फैसले की जानकारी पूरी दुनिया को दी। बयान में बताया गया है कि अमेरिका अपने पेशावर वाणिज्य दूतावास के कामकाज को हमेशा के लिए समेट रहा है। अब तक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के साथ कूटनीतिक बातचीत और कामकाज की जो जिम्मेदारी पेशावर दूतावास के पास थी, वह अब सीधे इस्लामाबाद में स्थित अमेरिकी दूतावास को सौंप दी जाएगी। यह कदम बताता है कि अमेरिका पाकिस्तान के उस इलाके में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा चिंतित है। अधिकारियों की सुरक्षा के डर से उठाया यह कदम? इस अहम फैसले को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला हमारे राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा और संसाधनों के सही प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पेशावर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा की स्थिति हमेशा दुनिया के लिए चिंता का विषय रही है। ऐसे में अमेरिका अपने अधिकारियों की जान को किसी भी तरह के जोखिम में नहीं डालना चाहता है। दूतावास बंद करने का सीधा मतलब है कि अमेरिका अब वहां किसी भी तरह का खतरा मोल लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका से रिश्ते खत्म हो जाएंगे? इस बड़े सवाल का जवाब देते हुए अमेरिका ने कहा है कि पेशावर में दूतावास बंद होने का मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान के साथ उसके कूटनीतिक रिश्ते खत्म हो रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को लेकर उसकी नीतियां और प्राथमिकताएं पहले की तरह ही मजबूत और स्थिर रहेंगी। अमेरिका खैबर पख्तूनख्वा के लोगों और वहां के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत करता रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और अमेरिकी लोगों के हितों को आगे बढ़ाना है। शहरों में काम करते रहेंगे अमेरिकी अधिकारी? पेशावर में वाणिज्य दूतावास बंद होने के बाद भी अमेरिका का कूटनीतिक मिशन पाकिस्तान में काम करता रहेगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने पूरा भरोसा दिलाया है कि अमेरिका का मिशन पाकिस्तान में बाकी जगहों पर पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में मौजूद अमेरिकी दूतावास और राजनयिक पद पहले की तरह ही अपना काम करते रहेंगे। इन तीनों बड़े शहरों के जरिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते आगे बढ़ाए जाएंगे। इसलिए पेशावर से हटने के बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान में कूटनीतिक मौजूदगी पूरी मजबूती के साथ बनी रहेगी।

चीनी विदेश मंत्री की ईरानी समकक्ष से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों और प. एशिया संकट पर चर्चा

बीजिंग, एजेंसी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को बीजिंग में अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से मुलाकात की। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इस बैठक की जानकारी दी। हालांकि, इसमें अधिक विवरण साझा नहीं किया

गया। अराघची की यह पहली चीन यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब पश्चिम एशिया में तनाव जारी है। इस बीच, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उम्मीद जताई कि चीन इस यात्रा के दौरान ईरान से होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण कम करने की बात करेगा और क्षेत्र में तनाव घटाने की दिशा में संदेश देगा। इससे पहले ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने जानकारी दी थी कि इस दौरे के दौरान अराघची अपने चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में जारी संकट समेत क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान अराघची चीन के अपने समकक्ष वांग यी के साथ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और मौजूदा वैश्विक स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि अराघची की यह यात्रा वांग यी के निमंत्रण पर हो रही है और दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। अराघची ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि यह यात्रा कई देशों के साथ जारी कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वह चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चीन से पहले तीन देशों का किया दौरा कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पाकिस्तान, ओमान और रूस का दौरा किया है। ये दौरे पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच बातचीत का हिस्सा हैं। पिछले महीने रूस दौरे के दौरान अराघची ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन ने कहा था कि रूस पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के लोग अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। इस मुलाकात में अराघची ने अमेरिका और इस्राइल से संघर्ष और हमलों पर भी विस्तार से चर्चा की। पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के हितों का समर्थन करेगा और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद करेगा। पाकिस्तान दौरे के दौरान अराघची ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इसके बाद ओमान की यात्रा में उन्होंने समुद्री सुरक्षा पर फोकस दिया।

AI अपनाने की अंधी दौड़ में कंपनियों पर मंडराया खतरा, बुनियादी ढांचे की कमी से बढ़ा साइबर अटैक का जोखिम

चेन्नई, एजेंसी। तकनीक की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में भारत की कई कंपनियां एक बहुत बड़े और गंभीर खतरे की तरफ बढ़ रही हैं। आज के समय में हर छोटी-बड़ी कंपनी अपने काम को आसान, तेज और आधुनिक बनाने के लिए कृत्रिम

बुद्धिमत्ता (एआई) का जमकर सहारा ले रही है। लेकिन, इस अंधी दौड़ में वे अपनी सबसे अहम चीज यानी बुनियादी सुरक्षा को पूरी तरह से भूलती जा रही हैं। कंपनियों के पास साइबर हमलों से बचने के लिए जो एक मजबूत और ठोस बुनियादी सुरक्षा ढांचा होना चाहिए, उसकी भारी कमी साफ नजर आ रही है। इसी लापरवाही के कारण कंपनियों पर बड़े साइबर हमलों का भारी खतरा मंडरा रहा है। यह चौंकाने वाला खुलासा जाने-माने सॉफ्टवेयर संगठन जोहो कॉर्प की एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है। जोहो कॉर्प द्वारा जारी की गई श्स्टेट ऑफ वर्कफोर्स पासवर्ड सिक्योरिटी रिपोर्ट-2026श में कंपनियों की साइबर सुरक्षा तैयारियों को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 93 प्रतिशत संगठन यह तो मानते हैं कि एआई का इस्तेमाल उनकी साइबर सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई यह है कि देश की हर तीन में से एक कंपनी अब तक श्जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्कश यानी आधुनिक साइबर सुरक्षा का ढांचा ही अपने यहां लागू नहीं कर पाई है। जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क का सीधा सा मतलब है किसी पर भी आसानी से भरोसा न करना और हर स्तर पर सुरक्षा की कड़ी जांच करना। इस अहम ढांचे के लागू न होने की वजह से ही शातिर साइबर ठगों के लिए इन कंपनियों के जरूरी डेटा में सेंध लगाना बहुत आसान होता जा रहा है। भारतीय कंपनियां साइबर हमलों से बचने के लिए क्या कर रहीं? टिगॉन एडवायजरी कॉर्प की तरफ से जोहो वॉल्ट के लिए दुनिया भर में किए गए इस विस्तृत वैश्विक सर्वे में एक बहुत बड़ा अंतर सामने आया है। यह अंतर भारतीय कंपनियों के सुरक्षा को लेकर उनके अति-आत्मविश्वास और उनकी असली तैयारियों के बीच का है। रिपोर्ट के अनुसार, 98 प्रतिशत भारतीय कंपनियां एआई पर आधारित नए सुरक्षा टूल्स को अपनाने की जोरदार योजना बना रही हैं। इसमें से 76 प्रतिशत कंपनियों का सबसे पहला ध्यान श्रियल-टाइम थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्सश पर लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वे ऐसी आधुनिक तकनीक चाहती हैं जो किसी भी साइबर खतरे को तुरंत पहचान ले और उसी वक्त उसका करारा जवाब भी दे सके। सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की इस तेज दौड़ में 56 प्रतिशत कंपनियों का ध्यान श्यूजर बिहेवियर एनालिटिक्सश पर है, यानी वे यह गहराई से समझना चाहती हैं कि सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है। वहीं, 55 प्रतिशत कंपनियां जोखिम पर आधारित श्एक्सेस कंट्रोल ऑटोमेशनश पर फोकस कर रही हैं, जिससे उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने आप बिना किसी इंसानी मदद के काम कर सके। लेकिन, इस पूरी अत्याधुनिक योजना में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन तकनीकों को अपनाने की चाहत तो बहुत है, लेकिन कंपनियों की जो सबसे बुनियादी सुरक्षा स्थिति है, वह अभी भी बहुत कमजोर बनी हुई है। बिना मजबूत नींव के ये तकनीकें बेअसर हैं। कंपनियां पहले ही हो चुकी साइबर हमलों का शिकार?

इस रिपोर्ट में एक और बहुत ही डराने वाला और कड़वा सच सामने आया है। सर्वे में यह स्पष्ट पता चला है कि लगभग 47 प्रतिशत कंपनियां पहले ही किसी न किसी तरह के गंभीर साइबर हमलों का शिकार हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन कंपनियों को सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी हैकर या दुश्मन से नहीं, बल्कि श्इनसाइडर थ्रेटश यानी अपने ही अंदरूनी लोगों से है। 23 प्रतिशत कंपनियों ने खुलकर माना है कि उन्हें अपने ही कर्मचारियों या सिस्टम से जुड़े लोगों से प्रमुख जोखिम बना हुआ है। इसके अलावा, 18 प्रतिशत खतरा रैनसमवेयर (डेटा चुराकर फिरौती मांगना) और 18 प्रतिशत खतरा इंसानी गलतियों (मानवीय त्रुटियों) से है।

प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।